सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 189, नई दिल्ली । बुधवार, 18 सितम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जीवन में जिसने अपनी जीभ को संभालना सीख लिया, वो जीवन को भी संभाल लेगा, क्योंकि जीभ का स्वाद स्वास्थ्य खराब करता है और वाणी संबंध खराब कराती है।

03 एलजी से मिले केजरीवाल, मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा; आतिशी होंगी सीएम
06 घर पर जेईई मेन 2025 की तैयारी कैसे करें
08 क्या बीजेपी में शामिल होंगे मनोज मुंतशिर?

दिल्ली परिवहन विभाग के आला अधिकारी द्वारा फिर से प्रमुख तकनीकी पद पर आसीन किया गया गैर तकनीकी अधिकारी

संजय बाटला

नई दिल्ली। जिस कार्यालय) शाखा द्वारा दिल्ली परिवहन विभाग और अन्य सरकारी विभागों के वाहनों की जांच कर उनको वाहन की जरूरत अनुसार कार्यकराने के आदेश पारित किए जाते हैं वहा आसीन किया गैर तकनीकी अधिकारी

जिस कार्यालय/ शाखा से दिल्ली में पंजीकृत व्यवसायिक बिना परमिट वाले वाहनों को उनके द्वारा की गई गलती के लिए नोटिस और नियमानुसार कानूनी आदेश पारित किए जाते हैं वहा आसीन किया गैर तकनीकी अधिकारी

जिस कार्यालय/ शाखा से दिल्ली के व्यवसायिक वाहनों में अल्टरेशन कराने के आदेश पारित किए जाते हैं वहा आसीन किया गैर तकनीकी अधिकारी

जिस कार्यालय/ शाखा से दिल्ली के व्यवसायिक वाहनों को इंजन नम्बर और चेसिस नंबर खराबहोनेपर जांचकर नए इंजन नम्बर/चेसिस नंबर के आदेश जारी किए जाते हैं वहा आसीन किया गैर तकनीकी अधिकारी

जिस कार्यालय में बाहरी राज्यों से एनओसी लेकर दिल्ली में व्यवसायिक गतिविधियों के लिए वाहनों के आने पर उनको दिल्ली के व्यवसायिक वाहन के लिए नियमों आदेशों के तहत जांच करने के बाद दिल्ली में पंजीकरण के लिए आदेश जारी किए जाते हैं वहा आसीन किया गैर तकनीकी अधिकारी

ऐसा कार्यालय/ शाखा जहा 90 प्रतिशत से अधिक कार्य सिर्फ और सिर्फ एक मान्यता प्राप्त तकनीकी अधिकारी कर सकता है उस कार्यालय को किया तकनीकी अधिकारियों से पूर्ण रूप में मुक्त.

कितना दिल्ली की जनता की सुरक्षा के प्रति सजग है दिल्ली परिवहन विभाग का आला अधिकारी और साथ ही दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्य सचिव और उपराज्यपाल।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)
TOLWA
website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com
रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण
रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

एमपी व यूपी बॉर्डर पर चार दिन से लगा है 15 किलोमीटर का जाम, रोके गए 1000 ओवरलोड ट्रक व ट्रेलर

एमपी व यूपी बॉर्डर पर चार दिन से 15 किलोमीटर का जाम लगा है। बॉर्डर पर 1000 ओवरलोड ट्रक और ट्रेलर रोके गए हैं, लेकिन जाम से राहत नहीं मिली। जाम में फंसे लोग परेशानी हैं।

सोनभद्र। एमपी-यूपी बार्डर व सीमांचल क्षेत्र में राख ढुलाई में लगे करीब 1000 हजार ओवरलोड ट्रक एवं ट्रेलरों को रोक दिया गया है। रेणुकूट में 10 से 15 किलोमीटर क्षेत्र में चार दिनों से लगे जाम से मुक्ति दिलाने के लिए यह कोशिश की गई।

इलाके में आबाद पावर प्रोजेक्ट के साथ सीमावर्ती क्षेत्र मध्यप्रदेश में स्थित पावर प्लांट से उत्सर्जित राख राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की सड़क परियोजनाओं में खपाई जा रही है। राख के सड़क परिवहन को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के दिशानिर्देशों को दरकिनार किए जाने से हुए हालत से रूबरू होते हुए भी जिम्मेदारों की आंखें बंद हैं। इसका खामियाजा आम जनता के साथ मरीज, यात्री, कर्मचारी, छात्र भुगत रहे हैं।

चार दिन से लगे जाम के वजह से कई यात्रियों की ट्रेनें व फ्लाइटें छूटीं। कर्मचारी समय से कार्य स्थल व छात्र वक्त से स्कूल नहीं पहुंच सके। ऊजांचल की लाइफ लाइन माने जाने वाले शक्तिनगर-वाराणसी मार्ग पर जाम के कारण मरीजों को लेकर निकली एंबुलेंस को भी जाम के चलते रास्ता बदलना पड़ा।

जाम की गंभीर स्थिति पर सीएम सहित प्रदेश के मंत्री को तमाम ट्वीट के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। लेकिन, स्थिति इसलिए सामान्य नहीं हो पाई कि ओवरलोड ट्रक- ट्रेलर को जीरो प्वाइंट्स पर रोका नहीं जा सका था। इसके बाद अधिकारियों ने समस्या से निजात पाने के लिए ओवरलोड वाहनों को रोकने का कार्य शुरू किया। इसी के तहत शक्तिनगर पुलिस ने मध्यप्रदेश से राख लेकर यूपी में प्रवेश करने वाले वाहनों को रोक दिया।

शक्तिनगर स्थित पावर प्रोजेक्ट के राख बांध पर भी ट्रक व ट्रेलर को खड़ा करा दिया। इसके पीछे रेणुकूट क्षेत्र में लगे जाम को कारण बताया जा रहा है। शक्तिनगर के प्रभारी निरीक्षक कुमुद शेखर सिंह ने बताया कि आदेश के बाद वाहनों को खड़ा करा दिया गया है। जाम की स्थिति सामान्य होने पर वाहनों को छोड़ा जाएगा।

गिट्टी, बालू के लिए नियम, राख में मनमानी

शासन स्तर से मिले निर्देश पर गिट्टी, बालू के ओवरलोड पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई। इसमें तय किया गया कि जिस जगह से वाहनों को ओवरलोड किया गया, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके चलते गिट्टी व बालू की ओवरलोड ढुलाई काफी हद तक रुक गई। इसके विपरीत राख की ढुलाई व लदान स्थल पर ओवरलोड करने के मामले में जिम्मेदारी तय नहीं किए जाने से लापरवाही का सिलसिला जारी है।

नौ वाहनों के खराब होने से लगा लंबा जाम

हाथीनाला से अनपरा के बीच में जगह-जगह नौ वाहनों के खराब होने के कारण लंबा जाम लगा हुआ है। एमपी बॉर्डर पर एक हजार वाहनों को रोके जाने के बाद भी जाम से राहत नहीं मिली। वाराणसी-शक्तिनगर राजमार्ग पर धड़ल्ले से चल रही राख लदी ओवरलोड वाहनों से जगह-जगह राख गिरने से भी जाम की समस्या बन जाती है। वहीं चढ़ाई वाले इलाकों में वाहनों के खराब होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

रोडवेज बस चालक की पिटाई

रेणुकूट क्षेत्र में वाराणसी-शक्तिनगर राजमार्ग मार्ग पर चार दिनों से जाम लगा हुआ है। शनिवार की रात में पुलिस जाम खुलवाने में जुटी थी। इस बीच तुर्रा के स्थानीय युवकों ने एक रोडवेज बस चालक की पिटाई कर दी। उस समय बस शक्तिनगर की तरफ जा रही थी। रोडवेज चालक को लहूलुहान स्थिति में अस्पताल ले जाकर उपचार कराया गया।

दिल्ली मेट्रो में यात्रियों को नहीं चलेगा पता, बिना नजर आए पुलिसकर्मियों की उनपर रहेगी नजर

दिल्ली मेट्रो में यात्रियों की सुरक्षा के लिए दिल्ली मेट्रो पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। अब संवेदनशील मेट्रो स्टेशनों पर सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी गश्त करेंगे। भीड़ के साथ घुलकर पुलिसकर्मी आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखेंगे और तुरंत कार्रवाई करेंगे। इस कदम से यात्रियों को सुरक्षित माहौल मिलेगा। 190 मेट्रो स्टेशनों की जांच में 32 स्टेशनों पर चोरी छेड़खानी और अन्य आपराधिक वारदातें अधिक पाई गईं।

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली मेट्रो पुलिस ने कुछ बड़े व भीड़भाव वाले मेट्रो स्टेशन समेत संवेदनशील मेट्रो स्टेशनों पर सादे कपड़ों में गश्त करने का निर्णय लिया है। मेट्रो पुलिस ने हाल ही में सर्वे के बाद यह कदम उठाया है।

राजधानी में हाल के महीनों में यात्रियों की संख्या में काफी वृद्धि देखी गई है, जिससे अपराध रिपोर्ट में भी वृद्धि हुई है। 190 मेट्रो स्टेशनों की जांच में 32 स्टेशनों पर चोरी, छेड़खानी और अन्य आपराधिक वारदातें अधिक पाई गईं। इनमें कश्मीरी गेट, राजीव चौक, सीलमपुर, आनंद विहार और कालकाजी आदि शामिल हैं।

भीड़ के साथ घुलेंगे पुलिसकर्मी

संयुक्त पुलिस आयुक्त (परिवहन रेंज) विजय सिंह ने बताया कि उनका लक्ष्य यात्रियों को सुरक्षित वातावरण देना है। उन्होंने कहा भीड़ के साथ घुल मिलकर पुलिसकर्मी अधिक प्रभावी ढंग से आपराधिक गतिविधियों को रोक सकते हैं और घटनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया दे सकते हैं।

CISF और दिल्ली पुलिस के हवाले सुरक्षा

मेट्रो रेल की सुरक्षा की देखरेख सीआईएसएफ (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) और दिल्ली पुलिस करती हैं। सीआईएसएफ तलाशी और जांच करती हैं, वहीं मेट्रो पुलिस किसी तरह की वारदात होने पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करती है। पुलिस मेट्रो परिसर के अंदर व ट्रैक पर भी गश्त करती है। मेट्रो परिसर में 16 मेट्रो थाने हैं। डीसीपी स्तर के अधिकारी यूनिट के प्रमुख हैं।

विजय सिंह ने कहा कि बढ़े हुए सुरक्षा उपायों में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए प्लेटफार्मों और ट्रेनों पर महिला अधिकारियों की दृश्यता में वृद्धि भी शामिल होगी।

इसके अतिरिक्त पुलिस संदिग्ध व्यवहार पर नजर रखने और संभावित खतरों की पहचान करने के लिए तकनीक का लाभ उठाएगी।

इसी सप्ताह से शुरू होगी तैनाती

योजना के अनुसार, प्रवेश द्वार पर एक पुलिस अधिकारी तैनात किया जाएगा, जबकि महिला पुलिसकर्मी सहित दो-तीन कर्मी पीक आवर्स के दौरान प्लेटफार्मों और ट्रेनों पर नजर रखेंगे। सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों की तैनाती इसी सप्ताह से शुरू हो सकती है। पुलिस आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली मेट्रो में इस साल अब तक चोरी के 3,952 मामले सामने आए हैं।

परिवहन विभाग : कर्मियों को ड्यूटी में पहनना होगा बैज

जिला मुख्यालयों पर अक्सर देखा जाता है कि जितना लाभार्थी नहीं पहुंचे होते हैं, उसे कहीं ज्यादा ऐसे लोगों की भीड़ होती है, जो जनता को लूटने के लिए वहां पहुंचे होते हैं. परिवहन विभाग ने इस दलाली राज से परिवहन कार्यालयों को मुक्ति दिलाने के लिए नयी निर्देशिका जारी की है. नयी गाइडलाइन के मुताबिक, विभाग के सभी अधिकारियों को अपने गले में फोटो पहचान पत्र लटकाना होगा. साथ ही, जिन लोगों को वर्दी में काम करना है, उन्हें इसका पालन करने के लिए कहा गया है.

कोलकाता। जिला मुख्यालयों पर अक्सर देखा जाता है कि जितना लाभार्थी नहीं पहुंचे होते हैं, उसे कहीं ज्यादा ऐसे लोगों की भीड़ होती है, जो जनता को लूटने के लिए वहां पहुंचे होते हैं. परिवहन विभाग ने इस दलाली राज से परिवहन कार्यालयों को मुक्ति दिलाने के लिए नयी निर्देशिका जारी की है. नयी गाइडलाइन के मुताबिक, विभाग के सभी अधिकारियों को अपने गले में फोटो पहचान पत्र लटकाना होगा. साथ ही, जिन लोगों को वर्दी में काम करना है, उन्हें इसका पालन करने के लिए कहा गया है. साथ ही आरटीओ कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों के नाम और पद के साथ उनके दायित्व की सूची वाला एक बोर्ड लगाने को कहा गया है.

परिवहन विभाग से सचिव सौमित्र मोहन द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, उपरोक्त बोर्ड ऐसे स्थान पर लगाना होगा, जहां, सभी को सपष्ट दिखे. सचिव सौमित्र मोहन ने हाल ही में परिवहन विभाग के विभिन्न कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर वाहन पंजीकरण, वाणिज्यिक वाहन परमिट कार्य, वाहन स्वास्थ्य जांच और वाहन से संबंधित व्यवसाय परमिट में पारदर्शिता बढ़ाने और सेवा संबंधी कार्यों में तेजी लाने के लिए 20 सूत्री निर्देश जारी किया है।

पीजीआई बस विवाद: हरियाणा ने तीसरी बार किया मना, कहा- निजी कंपनियों की बसें चल रही, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं

विवाद 10 अगस्त से चंडीगढ़-हरियाणा में विवाद शुरू हुआ था, जब सीटीयू यूनियन के सदस्यों को पता चला कि पंचकूला ने पीजीआई के लिए लोकल बस सेवा शुरु की है। 11 अगस्त को सेक्टर-16 के रोज गार्डन के पास सीटीयू की यूनियन ने बस को रोक दिया और एसटीए ने चालान काटने के साथ बस को जब्त कर लिया। इसके बाद से चंडीगढ़-पंचकूला में ठन गई।

पंचकूला और कालका से पीजीआई के चल रही इलेक्ट्रिक बस को रोकने से हरियाणा ने तीसरी बार मना कर दिया है। इस बार हरियाणा ट्रांसपोर्ट विभाग ने चंडीगढ़ के स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की मंशा पर ही सवाल उठा दिए हैं।

चंडीगढ़ की तरफ से तीसरी बार लिखे पत्र पर जवाब देते हुए हरियाणा ने लिखा कि चंडीगढ़ में कई निजी कंपनियों की बसें चल रही हैं। कई स्टॉपेज बनाए हुए हैं। क्या एसटीए ने उन पर कार्रवाई की है। साथ ही कहा है कि पीजीआई तक जाने वाली ई-बस जारी रहेगी।

एक माह से बना है विवाद

यूटी प्रशासन के एसटीए और हरियाणा के एससीबीएसएल के बीच पिछले करीब एक महीने से विवाद बना हुआ है। कालका और पंचकूला से पीजीआई के लिए हरियाणा की तरफ से रोजाना ई-बसें चलाई जा रही हैं। यूटी प्रशासन ने इसे अवैध बताया है और रोकने के लिए तीन बार पत्र लिख चुका है। हर बार जवाब में हरियाणा ने बस रोकने से मना किया है।

एसटीए को भेजे तीसरे पत्र में एससीबीएसएल के सीईओ ने एसटीए की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। पत्र में लिखा कि कई प्राइवेट ऑपरेटर जैसे, निओगो, बालाजी बस सर्विस, विजय बस सर्विस, गजराज बस सर्विस आदि अन्य

राज्यों और शहरों से चंडीगढ़ के अंदर बस चला रहे हैं। यह शहर के अलग-अलग जगह पर सवारियों को बिठाते और उतारते हैं। पत्र में लिखा है कि यह सबको पता है कि निओगो नाम की इलेक्ट्रिक बस आईएसबीटी-43, ट्रिब्यून चौक और आईएसबीटी-17 के सामने भी रुकती हैं। यहां पर सवारियों को बैठाया जाता है और उतारा जाता है। क्या जिस नियमों का हवाला देकर हरियाणा की ई-बस को रोका जा रहा है। क्या उन्हीं नियमों के तहत इस निजी बस का चालान किया गया है।

साथ ही लिखा है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) की गाइडलाइन्स के अनुसार ई-बसों को परमिट से छूट प्राप्त है, इसलिए हरियाणा कि बस पीजीआई के लिए जारी रहेगी। चंडीगढ़ की तरफ से इसे अवैध तरीके से न रोका जाए और न ही चालान किया जाए।

कालका-पिंजौर से फिक्स 60 रुपये किराया

हरियाणा ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि कालका-पिंजौर से पीजीआई के लिए जो बस चल रही है, वो स्टेज कैरिज नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट कैरिज है क्योंकि कालका-पिंजौर से बस में बैठने वाली सवारियों से फिक्स 60 रुपये किराया वसूला जाता है, जबकि स्टेज कैरिज में बसें कई स्टॉप पर रुकती हैं और सवारियों को बिठाती और उतारती हैं।

नाम न छापने की शर्त पर परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्पष्टीकरण के लिए मोर्थ को मामला भेजा गया है। जवाब का इंतजार किया जा रहा है। वहीं, एसटीए के अधिकारी पिछले कई दिनों से नो कमेंट्स ही कह रहे हैं। हालांकि, एसटीए हरियाणा को चौथा पत्र भेजने की तैयारी में है। चंडीगढ़ गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन के महासचिव सतिंदर सिंह ने कहा कि अवैध बसों के खिलाफ एक बार प्रदर्शन कर चुके हैं। एसटीए के आश्वासन पर उनके रुख का इंतजार कर रहे हैं। अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी।

एसटीए के तीन पत्रों का असर नहीं, 10 अगस्त से चल रही बस

यूटी परिवहन विभाग के अधिकारियों का भी मानना है कि नियमों के हिसाब से लोकल रूट पर अन्य कोई बस नहीं चला सकता। एसटीए तीन बार हरियाणा को बस रोकने के लिए लिख चुका हैं लेकिन कोई असर नहीं पड़ा।

श्राद्ध करने से उतरता है पूर्वजों का ऋण, इन बातों का रखें ध्यान

डा. अनीष व्यास

ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि श्रद्धा से किया गया कर्म श्राद्ध कहलाता है। अपने पितरों के लिए श्रद्धा से किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध कहते हैं। उन्हें तृप्त करने की क्रिया को तर्पण कहा जाता है। तर्पण करना ही पिंडदान करना है।

पितृ पक्ष के दौरान दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। मान्यता है कि अगर पितर नाराज हो जाएं तो व्यक्ति का जीवन भी खुशहाल नहीं रहता और उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यही नहीं घर में अशांति फैलती है और व्यापार व गृहस्थी में भी हानि झेलनी पड़ती है। ऐसे में पितरों को तृप्त करना और उनकी आत्मा की शांति के लिए पितृ पक्ष में श्राद्ध करना जरूरी माना जाता है। पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर-जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि श्राद्ध के जरिए पितरों की तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है और पिंड दान व तर्पण कर उनकी आत्मा की शांति की कामना की जाती है। श्राद्ध से जो भी कुछ देने का हम संकल्प लेते हैं, वह सब कुछ उन पूर्वजों को अवश्य प्राप्त होता है। जिस तिथि में जिस पूर्वज का स्वर्गवास हुआ हो उसी तिथि को उनका श्राद्ध किया जाता है जिनकी परलोक गमन की तिथि ज्ञान न हो, उन सबका श्राद्ध अमावस्या को किया जाता है।

ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि शास्त्रों के अनुसार पितृगणों का श्राद्ध कर्म करने के लिए वर्ष में 96 अवसर मिलते हैं। साल के 12 माह में 12 अमावस्या तिथि को भी श्राद्ध किया जा सकता है। श्राद्ध कर्म करने से तीन पीढ़ियों के पूर्वजों को तर्पण किया जा सकता है। श्राद्ध तीन पीढ़ियों तक होता है। श्राद्ध पुत्र, पोता, भतीजा या भांजा करते हैं। जिनके घर में पुरुष सदस्य नहीं हैं, उनमें महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती हैं। पितृ पक्ष में सभी तिथियों का अलग-अलग महत्व है। जिस व्यक्ति की मृत्यु जिस तिथि पर होती है, पितृ पक्ष में उसी तिथि पर श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। पूर्णिमा तिथि से पितृ पक्ष आरंभ होता है। प्रतिपदा तिथि पर नाना-नानी के परिवार में किसी की मृत्यु हुई हो और मृत्यु तिथि ज्ञात न हो तो उसका श्राद्ध प्रतिपदा पर किया जाता है। पंचमी तिथि पर अगर किसी अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उसका श्राद्ध इस तिथि पर करना चाहिए। अगर किसी महिला की मृत्यु हो गई है और मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है तो उसका श्राद्ध नवमी तिथि पर किया जाता है। एकादशी पर मृत संन्यासियों का श्राद्ध किया जाता है। जिनकी मृत्यु किसी दुर्घटना में हो गई है, उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि पर करना चाहिए। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर ज्ञात-अज्ञात सभी पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो, उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है।

ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि श्रद्धा से किया गया कर्म श्राद्ध कहलाता है। अपने पितरों के लिए श्रद्धा से किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध कहते हैं। उन्हें तृप्त करने की क्रिया को तर्पण कहा जाता है। तर्पण करना ही पिंडदान करना है। भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण की अमावस्या तक कुल 16 दिन तक श्राद्ध रहते हैं। इन 16 दिनों के लिए हमारे पितृ सूक्ष्म रूप में हमारे घर में विराजमान होते हैं। श्राद्ध में श्रीमद्भागवत गीता के सातवें अध्याय का माहात्म्य पढ़कर फिर पूरे अध्याय का पाठ करना चाहिए। इस पाठ का फल आत्मा को समर्पित करना चाहिए। श्राद्धकर्म से पितृगण के साथ देवता भी तृप्त होते हैं। श्राद्ध-तर्पण हमारे पूर्वजों के प्रति हमारा सम्मान है। इसी से पितृ ऋण भी चुकता होता है। श्राद्ध के 16 दिनों में अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करें। इन दिनों में घर में 16 या 21 मोर के पंख अवश्य लाकर रखें। शिवलिंग पर जल मिश्रित दुग्ध अर्पित करें। घर में प्रतिदिन खीर बनाएं। भोजन में से सर्वप्रथम गाय, कुत्ते और कौए के लिए ग्रास अलग से निकालें। माना जाता है कि यह सभी जीव यम के काफी निकट हैं। श्राद्ध पक्ष में व्यसनों से दूर रहें। पवित्र रहकर ही श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्य भी वर्जित माने गए हैं। श्राद्ध का समय दोपहर में उपयुक्त माना गया है। रात्रि में श्राद्ध नहीं किया जाता। श्राद्ध के भोजन में बेसन का प्रयोग वर्जित है। श्राद्ध कर्म में लोहे या स्टील के पात्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पितृदोष जब शांत हो जाता है तो स्वास्थ्य, परिवार और धन से जुड़ी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं।

दिन का महत्व

जो पूर्णमासी के दिन श्राद्ध आदि करता है उसकी बुद्धि, पुष्टि, स्मरणशक्ति, धारणाशक्ति, पुत्र-पौत्रादि एवं ऐश्वर्य की वृद्धि होती। वह पर्व का पूर्ण फल भोगता है। प्रतिपदा धन-सम्पत्ति के लिए होती है एवं श्राद्ध करने वाले की प्राप्त वस्तु नष्ट नहीं होती। जो सप्तमी को श्राद्ध आदि करता है उसको महान यज्ञों के पुण्य फल प्राप्त होते हैं। अष्टमी को श्राद्ध करने वाला सम्पूर्ण समृद्धियां प्राप्त करता है। नवमी को श्राद्ध करने से ऐश्वर्य एवं मन के अनुसार अनुकूल चलने वाली स्त्री को प्राप्त करता है। दशमी तिथि का श्रद्धा मनुष्य ब्रह्मत्व की लक्ष्मी प्राप्त कराता है।

श्राद्ध विधि

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध करने की भी विधि होती है। यदि पूरे विधि विधान से श्राद्ध कर्म न किया जाए तो मान्यता है कि वह श्राद्ध कर्म निष्फल होता है और पूर्वजों की आत्मा अतृप्त ही रहती है। शास्त्रसम्मत मान्यता यही है कि किसी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण के जरिए ही श्राद्ध कर्म (पिंड दान, तर्पण) करवाना चाहिए। श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को तो दान दिया ही जाता है साथ ही यदि किसी गरीब, जरूरतमंद की सहायता भी आप कर सकें तो बहुत पुण्य मिलता है। इसके साथ-साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु-पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए। श्राद्ध करने के लिए सबसे पहले जिसके लिए श्राद्ध करना है उसकी तिथि का ज्ञान होना जरूरी है। जिस तिथि को मृत्यु हुई हो उसी तिथि को श्राद्ध करना चाहिए। लेकिन कभी-कभी ऐसी स्थिति होती है कि हमें तिथि पता नहीं होती तो ऐसे में आश्विन अमावस्या का दिन श्राद्ध कर्म के लिए श्रेष्ठ होता है क्योंकि इस दिन सर्वपितृ श्राद्ध योग माना जाता है। दूसरी बात यह भी महत्वपूर्ण है कि श्राद्ध करवाया कहां पर जा रहा है। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो घर पर भी इसे किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोज करवाना चाहिए. भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर भी उन्हें संतुष्ट करें।

श्राद्ध पूजा दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए. योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चारण करें और पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। इसके बाद जो भोग लगाया जा रहा है उसमें से गाय, कुत्ते, कौवे आदि का हिस्सा अलग कर देना चाहिए। इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए. मन ही मन उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए।

इन पांच जीवों का ही चुनाव क्यों किया गया है

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि पितृपक्ष शुरू हो चुके है और ऐसा माना जाता है कि इस दौरान हमारे पितर धरती पर आकर हमें आशीर्वाद देते हैं। पितृ पक्ष में पितरों का श्राद्ध करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे पितृ पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे निकट आते हैं और गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी के माध्यम से पितृ आहार ग्रहण करते हैं।

श्राद्ध के समय पितरों के लिए भी आहार का एक अंश निकाला जाता है, तभी श्राद्ध कर्म पूरा होता है। श्राद्ध करते समय पितरों को अर्पित करने वाले भोजन के पांच अंश निकाले जाते हैं गाय, कुत्ता, चींटी, कौवा और देवताओं के लिए।

कुत्ता जल तत्त्व का प्रतीक है, चींटी अग्नि तत्व का, कौवा वायु तत्व का, गाय पृथ्वी तत्व का और देवता आकाश तत्व का प्रतीक हैं। इस प्रकार इन पांचों को आहार देकर हम पंच तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।. केवल गाय में ही एक साथ पांच तत्व पाए जाते हैं। इसलिए पितृ पक्ष में गाय की सेवा विशेष फलदाई होती है।

कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि पितरों को खुश रहने के लिए श्राद्ध के दिनों में विशेष कार्य करना चाहिए वही इस दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है।

1. श्राद्ध करने के लिए ब्रह्मवैवर्त पुराण जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि दिवंगत पितरों के परिवार में या तो ज्येष्ठ पुत्र या कनिष्ठ पुत्र और अगर पुत्र न हो तो नाती, भतीजा, भांजा या शिष्य ही तिलांजलि और पिंडदान देने के पात्र होते हैं।

2. पितरों के निमित्त सारी क्रियाएं गले में दाये कंधे मे जनेउ डाल कर और दक्षिण की ओर मुख करके की जाती है।

3. कई ऐसे पितर भी होते है जिनके पुत्र संतान नहीं होती है या फिर जो संतान हीन होते हैं। ऐसे पितरों के प्रति आदर पूर्वक अगर उनके भाई भतीजे, भांजे या अन्य चाचा ताउ के परिवार के पुरूष सदस्य पितृपक्ष में श्रद्धापूर्वक व्रत रखकर पिंडदान, अन्नदान और वस्त्रदान करके ब्राह्मणों से विधिपूर्वक श्राद्ध कराते है तो पितर की आत्मा को मोक्ष मिलता है।

4. भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक अनीष व्यास ने बताया कि श्राद्ध के दिन लहसुन, प्याज रहित सात्विक भोजन ही घर की रसोई में बनना चाहिए। जिसमें उड़द की दाल, बडे, चावल, दूध, घी से बने पकवान, खीर, मौसमी सब्जी जैसे तोरई, लौकी, सीतफल, भिण्डी कच्चे केले की सब्जी ही भोजन में मान्य है। आलू, मूली, बैंगन, अरबी तथा जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियां पितरों को नहीं चढ़ती है।

5. श्राद्ध का समय हमेशा जब सूर्य की छाया पैरो पर पड़ने लग जाए यानी दोपहर के बाद ही शास्त्र सम्मत है। सुबह-सुबह अथवा 12 बजे से पहले किया गया श्राद्ध पितरों तक नहीं पहुंचता है।

पितरों के लिए श्रद्धा एवं कृतज्ञता प्रकट करने वाले को कोई निमित्त बनाना पड़ता है। यह निमित्त है श्राद्ध। पितरों के लिए कृतज्ञता के इन भावों को स्थिर रखना हमारी संस्कृति की महानता को प्रकट करता है। देवस्मृति के अनुसार श्राद्ध करने की इच्छा करने वाला व्यक्ति परम सौभाग्य पाता है।

एकादशी का श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ दान

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास ने बताया कि श्राद्ध न किया जाए तो पितर गृहस्थ को दारुण शाप देकर पितृलोक लौट जाते है। एकादशी का श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ दान है। वह समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त कराता है। उसके सम्पूर्ण पापकर्मों का विनाश हो जाता है तथा उसे निरंतर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।

वहीं, द्वादशी तिथि के श्राद्ध से राष्ट्र का कल्याण तथा प्रचुर अन्न की प्राप्ति कही गई है। त्रयोदशी के श्राद्ध से संतति, बुद्धि, धारणाशक्ति, स्वतंत्रता, उत्तम पुष्टि, दीर्घायु तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है।

ऐसे करें श्राद्ध

- श्राद्ध करने के लिए किसी ब्राह्मण को आमंत्रित करें, भोज कराएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी दें।

- श्राद्ध के दिन अपनी सामर्थ्य या इच्छानुसार खाना बनाएं।

- आप जिस व्यक्ति का श्राद्ध कर रहे हैं उसकी पसंद के मुताबिक खाना बनाएं जो उचित रहेगा।

- मान्यता है कि श्राद्ध के दिन स्मरण करने से पितर घर आते हैं और अपनी पसंद का भोजन कर तृप्त हो जाते हैं।

- खाने में लहसुन-प्याज का इस्तेमाल न करें।

- शास्त्रों में पांच तरह की बलि बताई गई हैं: गौ (गाय) बलि, श्वान (कुत्ता) बलि, काक (कौवा) बलि, देवादि बलि, पिपीलिका (चींटी) बलि

मां लक्ष्मी का प्रिय रत्न पहनने से दूर होती है आर्थिक तंगी, धन की नहीं रहती है कमी

अनन्या मिश्रा

रत्न शास्त्र में एक ऐसे रत्न के बारे में बताया गया है, जिसका सीधा संबंध मां लक्ष्मी से माना जाता है। इस रत्न को धारण करने से जातक पर मां लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद बना रहता है। यह मां लक्ष्मी का प्रिय रत्न होता है।

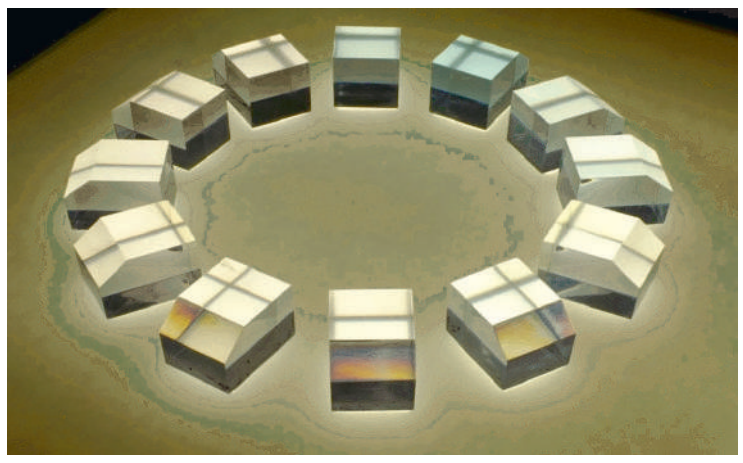

हिंदू धर्म में माना गया है कि अगर किसी व्यक्ति को धन संबंधित समस्याएं हैं, तो उसे मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। मां लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। ऐसे में मां लक्ष्मी की पूजा करने से जातक को आर्थिक स्थिति में लाभ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा रत्न शास्त्र में एक ऐसे रत्न के बारे में बताया गया है, जिसका सीधा संबंध मां लक्ष्मी से माना जाता है। इस रत्न को धारण करने से जातक पर मां लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद बना रहता है।

मां लक्ष्मी का प्रिय रत्न

रत्न शास्त्र के अनुसार, यह मां लक्ष्मी का प्रिय रत्न होता है। इसको धारण करने से व्यक्ति पर मां लक्ष्मी का हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। जातक को धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। यह रंगहीन और पारदर्शी स्टोन होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस रत्न को मां लक्ष्मी अपने कंठ में धारण करती हैं, इस कारण से इस रत्न को कंठ हार भी कहा जाता है।

मिलते हैं ये लाभ

रत्न शास्त्र के मुताबिक स्टफिक की माला पहनना ज्यादा शुभ होता है। इस रत्न को धारण करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और जातक को कभी धन की कमी नहीं होती है। स्फटिक को धारण करने से पारिवारिक कलह से मुक्ति मिलती है और इस रत्न का अधिक लाभ पाने के लिए इसे घर की तिजोरी में भी रख सकते हैं। इसको तिजोरी में इस तरह से रखें कि यह दक्षिण दिशा में हो और इसका मुख उत्तर दिशा में हो।

स्टफिक पहनने का नियम

शुक्रवार या बुधवार का दिन इस रत्न को धारण करना चाहिए। आप चाहें तो इस रत्न को अंगूठी या माला के तौर पर भी पहन सकते हैं। स्टफिक को धारण करने से पहले इसको गंगाजल से धो लें और फिर इसको मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। फिर ऊं श्रीं लक्ष्म्यै नमः मंत्र का 7 बार जाप करने के बाद ही इस रत्न को धारण करें।

बुजुर्गों को परेशान करती है सांस संबंधी बीमारियां, तो बचने के लिए इन टिप्स को जरुर फॉलो करें

आजकल बुजुर्गों में सांस संबंधी बीमारियां काफी आम हो गई है। दवाईयों के साथ ही बेहतर केयर भी जरुरी है। इस बदलते मौसम में इन बीमारियों का खतरा सबसे अधिक रहता है। आइए जानते हैं किस तरह से बचा जा सकता है।

उम्र के साथ-साथ कई बीमारियों का खतरा बना रहता है। उम्र बढ़ने के साथ, बीपी, शुगर, दिल की बीमारियां और जोड़ों के दर्द जैसी दिक्कते आम हो जाती है। बुढापे में सांस संबंधी बीमारियां अधिक होती हैं। सांस फूलना, सांस लेने में दिक्कत या श्वसन तंत्र के जुड़े इंफेक्शन बुजुर्गों को अधिक परेशान करते हैं। खासतौर पर बढ़ती हुई उम्र में और बदलते मौसम में सांस से जुड़ी दिक्कतों का खतरा अधिक रहता है। किन टिप्स की मदद से आप सांस संबंधी बीमारियों में बुजुर्गों की सही देखभाल करें।

इन टिप्स को फॉलो करें

- बुजुर्गों में होने वाली सांस संबंधी समस्याओं में देखभाल करने की अधिक जरुरत होती है क्योंकि कमजोर इम्यून सिस्टम के कारण, बुजुर्गों में इसका खतरा अधिक रहता है।

- फ्लू और न्यूमोनिया के वैक्सीनेशन भी जरुर लगवाएं। यह वैक्सीन कॉमन इंफेक्शन बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं

- बुजुर्गों के कमरे के आसपास साफ-सफाई रखना बहुत जरुरी होता है। यहां धूल-मिट्टी नहीं होनी चाहिए क्योंकि धूल-मिट्टी, प्रदूषण के कण और अन्य कई चीजों के कारण, श्वसन संक्रमण बढ़ सकते हैं।

- हाथों को साफ रखना काफी जरुरी है। इसके साथ ही, फ्लू सीजन में या भीड़भाड़ वाली जगह में बुजुर्गों को मास्क लगाकर रखना चाहिए ताकि इंफेक्शन से बचा जा सकता है।

- बुजुर्गों को एंटी-ऑक्सीडेंट्स, विटामिन-सी, विटामिन-डी और ओमेगा-3 फैटी एसिड्स से भरपूर डाइट, फेफड़ों और इम्यून सिस्टम के लिए काफी जरुरी है।

- स्वयं का हाइड्रेट रखना भी काफी जरुरी है और स्मोकिंग न करें व स्मोक वाली जगह में जाना अवॉइड करें।

- अपने क्षमता के अनुसार ही फिजिकल एक्टिविटी करें। इससे लंग्स हेल्थ में सुधार रहता है।

- इसके साथ ही हेल्थ चेकअप कराना काफी जरुरी है।

आश्लेषा नक्षत्र में जन्में लोगों का स्वभाव एकदम रहस्यमयी होता है

दिव्यांशी भदौरिया

ज्योतिष के अनुसार, आश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति पर बुध का प्रभाव होता है। गौरतलब है कि बुध का प्रभाव के कारण वाणी मधुर होती है। इस कारण इनकी बातों से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इस जन्म नक्षत्र में जन्में लोग काफी अहंकारी है।

जो राशियां आश्लेषा नक्षत्र से संबंधित होती है उनमें विष तत्व होने वजह से यह नक्षत्र अपने शत्रुओं को नष्ट करने के लिए विष उत्पन्न करने वाला होता है। ज्योतिष के मुताबिक, इस नक्षत्र में स्थित सभी ग्रहों के कारक तत्वों में विष होता है। जैसे कि, चतुर्थ भाव के स्वामी के चतुर्थ भाव में होने पर मानसिक शांति समाप्त हो सकती है। इसका सीधा संबंध परिवर्तन से भी होता है। जैसे सांप अपनी त्वचा को छोड़ते समय अपनी आंखें बंद होने के कारण शीत निद्रा में जाता है। उसी प्रकार आश्लेषा नक्षत्र में दृष्टि दयनीय होती है। इस नक्षत्र में मंगल नीच होता है, जो अपनी नकारात्मक ऊर्जा से कार्य करते हैं और बिना चोट पहुंचाए भी नुकसान पहुंचा देता है।

आश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुई लोगों का व्यक्तित्व

इस नक्षत्र में जन्में लोग चालबाजी करने वाले, अंडरवर्ल्ड और संदिग्ध लोगों जैसी सभी भूमिगत गतिविधियां इस नक्षत्र के अंतगर्त आती है। वहीं, इस नक्षत्र के देवता नाग है। आपको बता दें कि, आश्लेषा नक्षत्र में चार चरणों के अलग-अलग प्रभाव होते हैं।

पहला चरण

पहले चरण में धनु नवांश आता है और बृहस्पति द्वारा शसित होता है। इसमें जन्म लेने वाले व्यक्ति देखभाल करने वाले और भावुक होते हैं। यह लोग अक्सर दूसरों को भलाई करने के लिए तत्पर रहते हैं।

दूसरा चरण

यह चरण मकर नवांश में आता है और शनि के द्वारा शासित किया जाता है। वहीं, इसमें दूसरे चरण में जन्में लोग चतुर होते हैं। यह लोग अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं।

तीसरा चरण

तृतीया चरण इसका तीसरा चरण कुंभ नवांश का होता है और यह भी शनि द्वारा शासित किया जाता है। यह लोग काफी रहस्यमयी होते हैं।

चौथा चरण

चतुर्थ चरण इस नक्षत्र का चौथा चरण मीन नवांश होता है और बृहस्पति द्वारा शासित होता है। इस चरण में पैदा हुआ लोग कभी गलतियां नहीं करते और गलत होने की जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं।

रिश्ते के जुड़ाव को कमजोर कर देती हैं ये प्रतिक्रियाएं, कैसे?

बार-बार इन प्रतिक्रियाओं को दोहराने से समय के साथ हमारा पार्टनर, दोस्त या परिवार वाले हमसे दूर जा सकते हैं। इसलिए लोगों के लिए ये जरुरी है कि वह अपनी इन गलत प्रतिक्रियाओं के प्रति सचेत रहें और इनको नियंत्रित करना सीखें, ताकि महत्वपूर्ण रिश्ते बर्बाद होने से बच जाएं।

दूसरों के साथ हमारे व्यवहार में हमारी प्रतिक्रियाएं बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। कभी-कभी, गुस्से, हताशा या बिना सोचे-समझे हम बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दे देते हैं। इस दौरान हम ऐसी बातें कह सकते हैं या कर सकते हैं, जो दूसरों को चोट पहुँचाती हैं या उन लोगों के साथ हमारे रिश्ते को खराब कर देती है, जिनकी हम परवाह करते हैं। इस तरह की प्रतिक्रियाएं गलतफहमियां भी पैदा कर सकती हैं, जो हमसे जुड़े लोगों को परेशान कर सकती है और यहां तक कि उनका भरोसा भी तोड़ सकती है। बार-बार इन प्रतिक्रियाओं को दोहराने से समय के साथ हमारा पार्टनर, दोस्त या परिवार वाले हमसे दूर जा सकते हैं। इसलिए लोगों के लिए ये जरुरी है कि वह अपनी इन गलत प्रतिक्रियाओं के प्रति सचेत रहें और इनको नियंत्रित करना सीखें, ताकि महत्वपूर्ण रिश्ते बर्बाद होने से बच जाएं।

गलत प्रतिक्रियाएं, जो अक्सर लोग गुस्से और हताशा में देते हैं

बहस के दौरान चिल्लाना: जब हम चिल्लाते हैं, तो इससे दूसरे व्यक्ति के दिल में डर बैठ सकता है या उन्हें ठेस पहुंच सकती है। पार्टनर पर चिल्लाने से समस्या को हल नहीं किया जा सकता। इसके बजाय, यह बहस को और भी बदतर बना देता है, इतना बदतर कि रिश्ते को ठीक करना मुश्किल हो सकता है।

चुप रहकर साइलेंट ट्रीटमेंट देना: परेशान होने पर हमारा किसी से बात करने का मन नहीं करता, जो मानव स्वभाव है। लेकिन ऐसे समय में पार्टनर से बात न कर के उन्हें अनदेखा करने से उन्हें अकेला महसूस होगा, जिससे वह भ्रमित महसूस कर सकते हैं। इससे आपकी समस्या तो हल नहीं होगी, लेकिन आपका पार्टनर आपसे जरूर दूर चला जाएगा। बेहतर रहेगा परेशान होने पर अपने पार्टनर से स्पेस की मांग करें।

फीडबैक मिलने पर रक्षात्मक प्रतिक्रिया करना: समस्याओं को हल करने के लिए सुनना और समझना पड़ता है। जब आपका पार्टनर आपको किसी बात पर फीडबैक दे रहा है तो रक्षात्मक बनने की बजाय उन्हें सुनने की कोशिश करें। फीडबैक मिलने पर रक्षात्मक प्रतिक्रिया जैसे परेशान होना या गुस्सा हो जाने से समस्याओं को सुधारना या ठीक करना मुश्किल हो जाता है। इससे दूसरे व्यक्ति को ऐसा महसूस हो सकता है कि आप उनके विचारों की परवाह नहीं करते हैं।

बहस में पिछली गलतियों को सामने लाना: किसी नई बहस के दौरान पिछली गलतियों का जिक्र करना कुछ ऐसा है, जो पार्टनर को बुरा और फंसा हुआ महसूस करा सकता है। यह वर्तमान के मुद्दे और ज्यादा बड़ा बना सकता है, जिसे सुझाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा इससे आपके पार्टनर के विश्वास को ठेस पहुंचा सकती है।

अपनी भावनाओं के लिए अपने पार्टनर को दोषी ठहराना: दूसरों पर गलतियां मढ़ना आसान है और गुस्से में आमतौर पर लोग यहीं करते हैं। अपने दुख और गुस्से के लिए अपने पार्टनर को जिम्मेदार ठहराना, उन्हें दोषी महसूस करा सकता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं।

छोटी-छोटी समस्याओं पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया करना: छोटी-छोटी समस्याओं पर किसी को भी गुस्सा आ सकता है, लेकिन इनपर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देने से रिश्ते को तनावपूर्ण बना सकता है। इससे पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि वे कुछ भी सही नहीं कर सकते।

बड़ी हरकतों के बाद माफी मांगने से इनकार करना: जब लोग कुछ गलत करने के बाद माफी नहीं मांगते हैं, तो इससे उनके पार्टनर की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है और उनका भरोसा टूट सकता है। माफी मांगने से रिश्ते को सुधारने में मदद मिलती है क्योंकि यह दिखाता है कि हम अपने पार्टनर की परवाह करते हैं।

अपनी इन प्रतिक्रियाओं को कैसे बदलें?

रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और कोच कस्तूरी ने बताया कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके, आप अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं, बजाय इसके कि वे आपको नियंत्रित करें। जब आप शांत होते हैं, तो आप भड़कने या चुप रहने के बजाय सोच-समझकर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। भावनात्मक विनियमन आपको क्रोध या हताशा से घिरे बिना स्थितियों को अधिक स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है। उन्होंने आगे कहा कि यह आपके साथी के साथ स्वस्थ संचार बनाता है, आपकी चिंताओं को सुना जाता है, और मुद्दे तेजी से हल हो जाते हैं। आप अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे, और आपका रिश्ता मजबूत होगा क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाएं समझ से आएंगी, आवेगपूर्ण भावना से नहीं।

एलजी से मिले केजरीवाल, मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा; आतिशी होंगी सीएम

अरविंद केजरीवाल का अब दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल खत्म हो गया। उन्होंने सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया और राजनिवास पहुंचकर एलजी वीके सक्सेना को सौंपा। इसके साथ ही अब आतिशी नई मुख्यमंत्री बनेंगी। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के साथ ही केजरीवाल ने नई बनने जा रहीं मुख्यमंत्री आतिशी का पार्टी विधायक दल का प्रस्ताव भी एलजी को सौंपा।

नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वह शाम साढ़े 4 बजे राजनिवास पहुंचे और उपराज्यपाल वीके सक्सेना को इस्तीफा सौंपा। इस दौरान उनके साथ दिल्ली की होने वाली नई मुख्यमंत्री आतिशी और उनकी पूरी कैबिनेट भी साथ आए।

इस्तीफा सौंपने के बाद अरविंद केजरीवाल ने एलजी को विधायक दल की चुनी गईं नेता आतिशी का मुख्यमंत्री पद के लिए नाम का प्रस्ताव भी दे दिया। इसके बाद राजनिवास से बाहर आए और मीडिया से बगैर बात किए निकल गए। कैबिनेट मंत्री में गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन, सौरभ भारद्वाज भी साथ में थे।

जेल से निकलने के बाद की कुर्सी छोड़ने की घोषणा

बता दें कि आबकारी घोटाले से जुडे. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगभग छह माह तक तिहाड़ जेल में बंद रहने के बाद गत 13 सितंबर को जमानत पर बाहर आए आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने रविवार को दो दिन बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा है कि जब तक लोग उन्हें ईमानदारी का प्रमाणपत्र नहीं दे देंगे, तब तक वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे।

कौन हैं दिल्ली की नई सीएम आतिशी

दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से विधायक आतिशी आम आदमी पार्टी की नेता हैं और पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति (PAC) की सदस्य हैं। वर्तमान में आतिशी केजरीवाल सरकार में शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, संस्कृति और पर्यटन मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल रही हैं। इससे पहले उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की सलाहकार के रूप में भी काम किया है।

ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से ली शिक्षा

दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विजय कुमार सिंह और त्रिप्ता वाही के घर जन्मी आतिशी ने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली के स्प्रिंगडेल स्कूल (Springdale School) से की। इसके बाद उन्होंने सेंट स्टीफंस कॉलेज में इतिहास की पढ़ाई की, जहां वह दिल्ली विश्वविद्यालय में पहले स्थान पर रहीं।

इसके बाद Chevening scholarship पर मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय चली गईं। कुछ साल बाद उन्होंने एजुकेशन रिसर्च में रोड्स स्कॉलर के रूप में ऑक्सफोर्ड से अपनी दूसरी मास्टर डिग्री हासिल की।

कविता

आतिशी मार-लेना मैदान।

केजरीवाल ने बनाया प्लान,
इस्तीफे का भी किया ऐलान।
रहेगी बरकरार मेरी भी शान।
बोले आतिशी मार-लेना मैदान।
रह गए पीछे उनके खास साथी,
मनीष,संजय, सौरभ रहें बाकी।
सुनीता की बिना पद है झांकी।
मेरे पास है दिल्ली की जीतन।
नहीं काटने दूंगा ज्यादा फीतन।
सुनो मैं हरियाणे का सच्चा हूँ।
कुर्सी पकड़ के बैठा था मैं तो।
राजनीति का बहादुर बच्चा हूँ।
कितने मुझ पर लगाओ आरोप।
मैं पंजाब जैसा पौधा दूँगा रोप।
भले ही कोई मुझे कहे बेलदार,
यही है नाटक-नौटंकी खेलदार।
कहने दो उन्हें डमी है-डमी है।
भला आतिशी में कोई कमी हैं,
दूध, घी व मक्खन सब सही हैं।
चलो हरियाणा ही निकलते हैं,
हुड्डा जी को परेशान करते हैं।

संजय एम. तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)
इंदौर (मध्यप्रदेश)

अगर स्वाति मालीवाल को राज्यसभा में रहने का शौक है तो उन्हें भाजपा से राज्यसभा का टिकट लेना चाहिए- दिलीप पांडे

सुषमा रानी

नई दिल्ली, ''आप'' के वरिष्ठ नेता एवं विधायक दिलीप पांडे ने कहा कि अगर स्वाति मालीवाल में जरा भी शर्म है तो उन्हें राज्यसभा की सदस्यता से अपना इस्तीफ दे देना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने उनको टिकट देकर राज्यसभा में भेजा, लेकिन वह प्रतिक्रिया या बयान देने के लिए भाजपा से स्क्रिप्ट लेती हैं। यदि स्वाति मालीवाल को राज्यसभा में रहने का इतना ही शौक है तो उन्हें भाजपा से राज्यसभा का टिकट ले लेना चाहिए।

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधायक दिलीप पांडे ने कहा कि स्वाति मालीवाल ऐसी इंसान हैं, जो राज्यसभा जाने के लिए आम आदमी पार्टी से टिकट लेती हैं, लेकिन प्रतिक्रिया देने और बोलने के लिए स्क्रिप्ट भाजपा से लेती हैं। अगर उनमें थोड़ी भी शर्म है तो उन्हें आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद का टिकट छोड़ देना चाहिए। उन्हें राज्यसभा सदस्य के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और अब भाजपा के टिकट पर राज्यसभा जाने का रास्ता चुनना चाहिए। अगर उन्हें राज्यसभा में रहने का शौक है, तो उन्हें भाजपा से राज्यसभा का टिकट लेना चाहिए।

आतिशी को दिल्ली के लोगों, खासकर महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के समाधान के लिए काम करेंगी - देवेन्द्र यादव

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने नई मुख्यमंत्री आतिशी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्हें लोगों की समस्याओं का हल करने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि बिना कोई काम किये, हर विषय का राजनीतिकरण करना आम आदमी पार्टी की आदत बन चुकी है। उन्होंने कहा कि आतिशी सिर्फ तीन महीने के लिए मुख्यमंत्री बनी हैं और वह लोगों की समस्याओं को दरकिनार नहीं कर सकतीं, क्योंकि दिल्ली में महिलाओं पर अत्याचार बहुत बढ़े हैं, जिससे दिल्ली "रेप कैपिटल" बन गई है। यादव ने कहा, "आतिशी को महिलाओं की समस्याओं का समाधान करना चाहिए।" उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद इन्होंने एक भी वादे को पूरा नहीं किया है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद आतिशी जिनके पास 13 महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी है, क्या लंबित 11 सीएजी रिपोर्टों को विधानसभा में पेश करने की पहल करके सार्वजनिक करेंगी, क्योंकि इनमें सरकार के भ्रष्टाचार और धन के दुरुपयोग के राज छिपे है, आतिशी ने लंबे समय से दबाकर रखा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल कैबिनेट में लंबे समय से कोई महिला मंत्री नहीं थी और दो एस.सी. मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, उनके मंत्रालयों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, क्या दलितों के विषयों के संबध में किसी को जिम्मेदारी देंगी?

यादव ने बताया कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, दिल्ली में शीला दीक्षित के रूप में एक बहुत मजबूत महिला मुख्यमंत्री थीं। 15 वर्षों में शीला दीक्षित ने अभूतपूर्व विकास कार्य किए जिसको केजरीवाल सरकार ने अपनी नाकामियां के चलते कई साल पीछे धकेल दिया है और पिछले 11 वर्षों के कुशासन में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के बुनियादी ढांचे को ही बर्बाद करके रख दिया है।

उन्होने बताया कि ईमानदारी की बात करने वाले अरविन्द केजरीवाल ने इस्तीफा मजबूर होकर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिन शर्तों पर जमानत दी थी उनमें केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बार अस्थिर मुख्यमंत्री बनकर रह गए। उन्होंने कहा कि छह महीने पहले जब केजरीवाल को शराब घोटाले के सिलसिले में जेल भेजा गया था, तभी उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि भ्रष्टाचार का कलंक उन पर लग चुका है।

उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार लोगों के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। केजरीवाल अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए लोगों के पास जाने की बात कह रहे है, क्या उनके पास पिछले 12 वर्षों में उनके अधूरे वादों और बर्बाद होती दिल्ली के बारे में जवाब है जबकि दिल्ली की जनता के पास गंदा पानी, महंगी बिजली, ध्वस्त स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, पर्यावरण, डूबती दिल्ली, मरते लोग, टूटी और झील बन चुकी सड़कें आदि के संबध में कई सवाल हैं, जो केजरीवाल से पूछना चाहती है।

उन्होंने बताया कि जब भी वह कोई चुनाव हारते हैं, तो केजरीवाल को एक नई कहानी गढ़ने की आदत है, जैसे कि जब उन्होंने कहा था कि उन्हें "आतंकवादी" करार दिया जा रहा है, दिल्ली की जनता तय करेगी कि मैं आंतकवादी हूँ कि नही। लेकिन लोग अब उनके झूठ और नौटंकी पर विश्वास नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की नौटंकी और सरकार की विफलता पूरी तरह बेनकाब हो गयी है। उन्होंने कहा कि 2025 में दिल्ली में सरकार कांग्रेस बनाऐगी।

आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा का चुनाव अक्टूबर-नवंबर में कराने की मांग करती है- गोपाल राय

सुषमा रानी

नई दिल्ली। 17 सितंबर दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर चल रही तमाम चर्चाओं को मंगलवार को विराम लग गया। मौजूदा शिक्षा एवं वित्त मंत्री आतिशी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। ''आप'' के राष्ट्रीय संयोजक एवं सीएम अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई विधायक दल की बैठक में सर्व सम्मति से सभी विधायकों ने खड़े होकर आतिशी को अपना नेता चुन लिया। ''आप'' के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत ही घिनौना राजनीतिक षड्यंत्र रचकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पार्टी के अन्य नेताओं के ऊपर झूठे आरोप लगाए, उन्हें जेल भेजा और उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाकर दिल्ली सरकार को तोड़ने की कोशिश की। केजरीवाल ने दिलेरी के साथ मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया और जनता की अदालत में जाने का ऐलान किया। अब चुनाव तक दिल्ली के मुख्यमंत्री की ज़िम्मेदारी आतिशी जी को दी गई है।

मनीष सिसोदिया ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि दिल्ली की भावी मुख्यमंत्री आतिशी के हिस्से में आज मुख्यतः दो काम हैं। पहला, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के इस्तीफ़े से और मोदी जी के षड्यंत्र से बेहद आहत हैं। कई लोग रो रहे हैं और वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल वापस सीएम बनें। आतिशी को दिल्ली के दो करोड़ लोगों के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल को दोबारा दिल्ली का सीएम बनाना है। दूसरा, अगले कुछ महीनों में दिल्ली की जनता को परेशान करने के लिए भाजपा, सीएम केजरीवाल द्वारा दी गई सुविधाओं को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेगी। फ्री बिजली बंद करने की कोशिश करेगी, स्कूल-अस्पतालों को ख़राब करने की कोशिश करेगी। फ्री दवाई बंद करने की कोशिश करेगी और नालों व सीवर सफ़ाई का काम बंद करने की कोशिश करेगी। आतिशी की यह ज़िम्मेदारी है कि भाजपा के इस आतंक से दिल्ली की जनता की रक्षा करेंगी। मुझे पूरा यक़ीन हैं कि आतिशी इन कठिन ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगी। मेरी हार्दिक शुभकामनाए उनके साथ है।

गोपाल राय ने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री ने यह कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर इस्तीफा दे दें, ताकि दिल्ली सरकार को गिराया जा सके। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के हितों में काम को जारी रखने के लिए निर्णय लिया कि जेल के अंदर इस्तीफा नहीं देंगे और जेल में रहकर सरकार चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने जेल से सरकार चलाई भी। अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी ताकत ईमानदारी की ताकत है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी ईमानदारी की ताकत से दिल्ली में इतना काम किया कि आज भारत की कोई भी राज्य सरकार नहीं कर पाई है। भाजपा द्वारा अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी के उपर कीचड़ उछाला गया। इसी के मद्देनजर सीएम अरविंद केजरीवाल ने जेल से आने के बाद यह निर्णय लिया कि देश की सुप्रीम अदालत ने हमें जेल से बाहर किया है, लेकिन हम जनता की अदालत में जाएंगे। दिल्ली के लोग जब तक दोबारा उन्हें समर्थन नहीं देते हैं, तब तक दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे।

गोपाल राय ने कहा कि इन परिस्थितियों में जब अरविद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा देने का निर्णय लिया। इसी परिप्रेक्ष्य में मंगलवार को विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि अगले चुनाव तक दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी रहेंगे। आम आदमी पार्टी चाहती है कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव अक्टूबर-नवंबर में कराए जाएं। जब तक चुनाव नहीं होता है और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तब तक के लिए आतिशी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित हुआ है।

गोपाल राय ने कहा कि आतिशी को सभी विधायकों की तरफ से मुख्य रूप से दो जिम्मेदारी दी गई है। पहला, दिल्ली के दो करोड़ लोगों के साथ मिलकर भाजपा के सारे रूकावटों के बावजूद काम जारी रखेंगे। दूसरा, भाजपा अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों के लिए जितने काम किए, उन सभी को रोकना चाहती है। भाजपा फ्री बिजली, पानी रोकना चाहती है। सरकारी स्कूलों को खराब करना चाहती है। मोहल्ला क्लीनिक बंद करना चाहती है, महिलाओं की बस यात्रा और बुजुर्गों की तीर्थयात्रा को रोकना चाहती है। भाजपा ने दिल्ली के बुजुर्गों की पांच महीने तक पेंशन रोक दी थी। आतिशी को जिम्मेदारी की गई है कि दिल्लीवालों के काम को रोकने की भाजपा के सारे षड़यंत्रों को विफल करना है। हम भाजपा के षड़यंत्रों से लड़ रहे थे। इसलिए नए मुख्यमंत्री को इस संघर्ष को जारी रखने की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा और उसकी सरकार के षड़यंत्रों से दिल्ली के कामों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारियों को लेकर नई सरकार का गठन होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लाल किला ग्राउंड में हेल्थ मेला व भव्य कार्यक्रम

सुषमा रानी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर लव कुश रामलीला कमेटी एवम सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लीला स्थल लाल किला ग्राउंड में दिव्यांगजन को भारत सरकार की एडिप योजना के अंतर्गत सांसद प्रवीन खंडेलवाल और लव कुश लीला के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने चार सौ मोटरराइजड ट्राइसाइकिल बेसखिया, दिव्यंगजन के लिए स्पेशल मोबाइल, कानो की मशीन, नजर के चश्मे, आदि निशुल्क प्रदान किए।

इस अवसर पर सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने कहा हम नर सेवा नारायण सेवा के सिद्धांत को मानते हैं इसी के अंतर्गत मोदी जी के जन्मदिन पर दिव्यांगजन, बुजुर्गों, महिलाओं, स्कूली छात्रों को लाभान्वित किया गया, उन्होंने लीला कमेटी का आभार व्यक्त किया कि आज के दिन लीला आयोजकों ने ऐसा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया।

लव कुश लीला कमेटी के प्रेसीडेंट अर्जुन कुमार ने कहा हम लीला आयोजन के साथ साथ पूरे साल सामाजिक सेवा से जुड़े अनेक कार्यक्रम करते है, उन्होंने बताया महाराजा अग्रसेन अस्पताल रोहिणी, तारा संस्थान, एलप्स के सहयोग से आंखों की जांच, नजर के चश्मे, कानो की मशीन का वितरण किया गया। सांसद प्रवीन खंडेलवाल के साथ अर्जुन कुमार व्हीलचेयर ,स्कूली बच्चों को स्कूल बैग, किताबे कापिया और एक हजार महिलाओं को साड़ी वितरण किया ।

इस शिविर में सहयोग और अपनी सेवाए प्रदान करने वाले सभी डॉक्टर्स, नर्स, सहयोगी संस्थाओं का कमेटी की और से पवन गुप्ता, सुभाष गोयल और सत्य भूषण जैन स्वागत किया और सभी को लीला कमेटी का प्रतीक चिन्ह भेंट प्रदान करके सम्मानित किया गया

इस मौके पर पर एक रंगारंग कल्चरल कार्यक्रम और विशाल भंडार का आयोजन भी किया गया।

'आप' अब सिसोदिया के कंट्रोल में, उनके कहने पर ही आतिशी' भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा का बड़ा दावा

दिल्ली को अपना नया सीएम मिल गया है। दिल्ली के विधायक दल के नेताओं ने सर्वसम्मति से Atishi को अपना नेता चुन लिया है। इसके साथ ही अब आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन जाएंगी। उनके सीएम बनाए जाने को लेकर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बड़ा दावा किया है कि आतिशी को मनीष सिसोदिया के दबाव में सीएम बनाया गया है।

नई दिल्ली। आतिशी को दिल्ली का नया सीएम बनाए जाने को लेकर भाजपा के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक बड़ा दावा किया है।

वीरेंद्र सचदेवा का दावा है कि आम आदमी पार्टी अब मनीष सिसोदिया के कंट्रोल में है और उन्हीं के कहने पर आतिशी को Delhi New CM बनाया गया है।

वीरेंद्र सचदेवा ने तमाम दावे किए हैं। उनका कहना है कि मनीष सिसोदिया के दबाव में केजरीवाल को Atishi को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा है। सचदेवा ने आगे कहा कि सिसोदिया पहले आतिशी को अधिक से अधिक विभाग दिलाए, अब CM बना दिया है। उन्होंने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी अब सिसोदिया के कंट्रोल में लगती है। वीरेंद्र सचदेवा ने आगे कहा, 'अरविंद केजरीवाल ने मजबूरी में आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया है क्योंकि वे चाह कर भी अपनी मन मर्जी का मुख्यमंत्री नहीं बनवा सके। मैं कह रहा हूं कि चेहरा बदल गया है लेकिन AAP का भ्रष्टाचारी चरित्र वही है।' आप के विधायक रह चुके और अब भाजपा के सदस्य कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर आतिशी को दिल्ली के लिए खतरनाक बताया है। कपिल ने ट्वीट किया है, 'आतिशी के परिवार ने आतंकवादी अफ़ज़ल गुरु की फांसी रुकवाने का प्रयास किया था। नक्सली मानसिकता को बैकडोर से दिल्ली पर थोपने का पाप केजरीवाल कर रहें हैं।'

कपिल ने आगे लिखा, 'आज आम आदमी पार्टी एक ऐसा CM चुन रही हैं जिसका अन्ना आंदोलन और इंडिया अगेंस्ट करप्शन से कोई नाता कभी नहीं रहा। दिल्ली की जनता एक नक्सली कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री को कभी स्वीकार नहीं करेगी।'

पंजाबी फिल्म 'सुच्चा सूरमा' का प्रमोशन हुआ दिल्ली में

सुषमा रानी

हाल ही में आनेवाली पंजाबी फिल्म 'सुच्चा सूरमा' का प्रमोशन करने के लिए इसके कलाकार दिल्ली पहुंचे। यहां के कनॉट प्लेस स्थित(ड्रामा) सिंधिया हाउस में आयोजित प्रमोशनल कार्यक्रम में पंजाबी फिल्मों के लीजेंड अभिनेता बब्बू मान भी मौजूद थे। यह फिल्म 20 सितंबर को रिलीज होगी।

हाल ही में रिलीज इसके ट्रेलर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त सराहना मिली है, क्योंकि 'सुच्चा सूरमा' के म्यूजिक एल्बम के ट्रेलर के तत्काल बाद रिलीज फिल्म का ट्रेलर अपने आप में एक रोमांचक सिनेमाई अनुभव का वादा करता है, जिससे फिल्म की लोकप्रियता में भी इजाफा हुआ है।

दरअसल, 'सुच्चा सूरमा' कोई साधारण फिल्म नहीं है। इसे पंजाब की साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्म के रूप में सराहा जा रहा है। पंजाबी फिल्म उद्योग के लिए पहली बार इसके निर्माताओं ने यह भी घोषणा की है कि सागा स्टूडियो और सेवन कलर्स की इस संयुक्त प्रस्तुति, यानी इस फिल्म की एडवांस बुकिंग इसकी रिलीज से एक सप्ताह पहले खोली जाएगी, ताकि उत्साही प्रशंसकों को समय से पहले अपनी सीट सुरक्षित करने का मौका मिल सके। वैसे, इसमें संदेह नहीं कि इस लोककथा की भव्यता का वास्तविक और सर्वोत्तम अनुभव थिएटर में ही मिलेगा।

इस फिल्म में मुख्य भूमिका कोई और नहीं बल्कि बब्बू मान निभाएंगे। अन्य प्रमुख भूमिकाओं में समीक्षा ओसवाल, रवनीत कौर, सुविंदर विक्की, सरबजीत चीमा, महाबीर भुल्लर, गुरिंदर मकना, गुरप्रीत तोती, गुरप्रीत रतोल, जगजीत बाजवा आदि नजर आएंगे। बता दें कि इस फिल्म में सभी अलग-अलग अभिनेताओं, असामान्य और सामान्य चेहरों द्वारा शानदार प्रदर्शन किया जाएगा। एक उच्चस्तरीय विषय और महान अभिनेताओं द्वारा निभाई गई भूमिकाएं अपने आप में एक अनूठी घटना बनने जा रही हैं। फिल्म का निर्देशन अमितोज मान ने किया है और इंद्रजीत बंसल ने इस फिल्म में डीओपी के रूप में काम किया है। 'सुच्चा सूरमा' का संगीत सागा म्यूजिक के आधिकारिक हैंडल पर जारी किया गया है।

यीडा की बल्ले-बल्ले, करोड़ों में लगी जमीन की बोली; क्या हैं ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी के रेट?

यमुना प्राधिकरण Yeida की मंगलवार को बल्ले-बल्ले हो गई। प्राधिकरण की जमीन 35 लाख रुपये वर्गमीटर की दर से बिकी है। इस दौरान एक हजार वर्गमीटर भूखंड की सबसे अधिक बोली 28 .28 करोड़ रुपये लगाई गई तो यीडा के अधिकारियों की भी हैरान हो गए। पढ़िए आखिर ग्रेटर नोएडा में भूखंडों की नीलामी से यीडा के अधिकारियों को कितना फायदा हुआ है।

ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण में एक वर्गमीटर जमीन की कीमत 35.3 लाख रुपये तक पहुंच गई है। प्राधिकरण में मंगलवार को कारपोरेट कार्यालय Corporate Office के लिए एक हजार वर्गमीटर भूखंड की सबसे अधिक बोली 28.28 करोड़ रुपये लगी है।

भूखंडों की नीलामी से प्राधिकरण को आरक्षित मूल्य 112.50 करोड़ के सापेक्ष 265.14 करोड़ रुपये मिलेंगे। यह राशि करीब 134 प्रतिशत अधिक है। कारपोरेट कार्यालय के लिए भूखंड की पहली योजना Bhukhand Yojana में मिली प्रतिक्रिया से प्राधिकरण के अधिकारी भी आश्चर्यचकित हैं।

उत्साहित हैं प्राधिकरण अधिकारी

YEIDA Plot Scheme यमुना प्राधिकरण ने 11 जुलाई को सेक्टर 22 ई में कारपोरेट कार्यालय के लिए एक-एक हजार वर्गमीटर के 45 भूखंड की योजना निकाली थी। इन भूखंडों के लिए मंगलवार को नीलामी की गई। उम्मीद से अधिक बोली लगने से प्राधिकरण अधिकारी उत्साहित हैं।

YEIDA Scheme प्राधिकरण ने प्रत्येक भूखंड के लिए 2.50 करोड़ रुपये निर्धारित किया था, लेकिन बोली लगाने वालों ने प्राधिकरण की उम्मीद से अधिक बोली लगाई। चैलेंजर कंप्यूटर लि. ने भूखंड संख्या ओ-64 के लिए 28.28 करोड़ रुपये तक बोली पहुंची।

ओ-69 भूखंड के लिए एलिक्स ग्लोबल प्रा. लि. ने 26.64 करोड़ रुपये बोली लगाकर इसे जीत लिया। ओ-59 भूखंड के लिए सनाश इंपेक्स प्रा. लि. ने 25.84 करोड़ रुपये बोली आई।

प्राधिकरण सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि 45 भूखंडों के लिए कुल आरक्षित मूल्य 112.50 करोड़ रुपये के सापेक्ष 265.14 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। यह 152.64 करोड़ रुपये अधिक है। इन भूखंडों के आवंटन से पांच सौ करोड़ का निवेश और पांच हजार लोगों के लिए रोजगार सृजन होगा।

पहली बार डायनामिक एलाटमेंट सिस्टम के तहत हुई नीलामी

प्राधिकरण ने नीलामी से आवंटित होने वाले भूखंडों के लिए डायनामिक एलाटमेंट सिस्टम लागू किया है। इसके तहत कारपोरेट कार्यालय के लिए भूखंडों की पहली बार बोली लगाई गई। डायनामिक एलाटमेंट सिस्टम के अंतर्गत आवेदक को योजना में शामिल सभी भूखंडों के लिए बोली लगाने का मौका मिलता है, लेकिन जैसे ही वह किसी भूखंड के सापेक्ष सबसे अधिक बोली लगाकर उसे हासिल कर लेता है, अन्य भूखडों के लिए वह बोली प्रक्रिया से बाहर हो जाता है।

गाजियाबाद में फिर गरजेगा बुलडोजर!

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन तेज-NHAI

परिवहन विशेष न्यूज

गदिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे (डीएमई) एनएच-9 और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे (ईपीई) परअतिक्रमण करने वालों की अब खैर नहीं। प्रशासन एक्शन की तैयारी कर रहा है। यहां पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है। एनएचएआई के अधिकारियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सबसे अधिक अतिक्रमण वाले जगहों पर एक्शन लिया जा रहा है। डीएमई और ईपीई का अतिक्रमण हटाने की तैयारी तेज हो रही है।

गाजियाबाद। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे (डीएमई), एनएच-9 और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे (ईपीई) पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए योजना बनाई जा रही है। एनएचएआई के अधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन दिनों सबसे अधिक अतिक्रमण वाले प्वाइंटस को चिन्हित किया जा रहा है।

इस सर्वे के बाद एनएचएआई की टीमें यूपी गेट से लेकर मेरठ तक डीएमई (DME) और एनएच-9 पर जल्द ही कार्रवाई की तैयारी में है। एनएचएआई (NHAI) के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। उनका दावा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग से अतिक्रमण हटाने को लेकर संयुक्त समिति का गठन किया जाएगा।

135 किलोमीटर लंबे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे (ईपीई) कुंडली-गाजियाबाद-पलवल (केजीपी) पर जगह जगह भारी वाहनों को खड़ा करके अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की भी योजना है। इस पूरे मार्ग पर 20 से अधिक स्थानों की वीडियोग्राफी कराई जा रही है।

अतिक्रमण के चलते उक्त मार्गों पर सुबह और शाम को घंटों यातायात जाम रहता है। कुछ स्थानों पर तो बस और ऑटो चालक बीच रोड़ पर खड़ा करके सवारी उतारने और बिठाने में लगे रहते हैं।

कई बार भारी वाहनों के खड़ा होने से सड़क हादसे भी हुए हैं। कंट्रोल रूम के माध्यम से मार्ग पर वाहनों को खड़ा करने, गलत दिशा में वाहन चलाने और पाबंदी के बाद दुपहिया को चलाने पर थोक के भाव चालान किये जा रहे हैं।

एनएच-9 पर संभावित अतिक्रमण वाले प्वाइंट्स

- यूपी गेट
- सेक्टर-62 नोएडा
- छिजारसी
- कनावनी कट
- विजयनगर
- एबीईएस कट
- लालकुआं
- डासना
- मसूरी
- भोजपुर
- परतापुर

ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे (EPE) पर संभावित अतिक्रमण वाले प्वाइंट्स

- कुंडली
- पलवल
- ग्रेटर नोएडा
- दादरी
- डासना
- दुहाई
- रेवडी रेवडा
- बडौत
- सोनीपत

नोएडा के बार में विदेशियों लड़कियों के डांस का वीडियो वायरल, लोगों ने उठाए सवाल तो आबकारी विभाग ने मांगा जवाब

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा के गार्डन गलेरिया मॉल में स्थित F Bar and Lounge में विदेशी युवतियों के डांस का वीडियो वायरल होने के बाद आबकारी विभाग हरकत में आ गया है। विभाग ने बार संचालकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो जुर्माना सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना को सार्वजनिक शालीनता और नियमों के उल्लंघन के तौर पर देखा जा रहा है।

नोएडा। सेक्टर-38ए स्थित गार्डन गलेरिया मॉल में एफ बार एंड लाउज में विदेशी युवतियों के नाचने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद हरकत में आए आबकारी विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने बार-बार के संचालकों अजीत कुमार शर्मा, कमल किशोर व सागर वर्मा मंगलवार को नोटिस जारी किया है और तीन दिनों के भीतर जवाब मांगा है।

अगर तय समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, तो बार के खिलाफ जुर्माना सहित अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

विदेशी युवतियों का डांस, उठ रहे सवाल

मामला तब सामने आया जब इंटरनेट मीडिया पर बार में विदेशी युवतियों के डांस का वीडियो तेजी से प्रसारित हुआ। इस वीडियो को लेकर कई शिकायतें की गईं। इस घटना को सार्वजनिक शालीनता और नियमों के उल्लंघन के तौर पर देखा जा रहा है। इस मामले ने शहर में बार और रेस्तरां पर निगरानी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

गार्डेन गलेरिया में 24 बार

गार्डेन गलेरिया में अभी 24 बार हैं, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। शनिवार और रविवार को भीड़ ज्यादा होती है। यहां युवतियों के साथ बड़ी संख्या में युवक आते हैं। यहां स्थित बार एंड रेस्तरां को खाद्य विभाग और आबकारी विभाग की ओर से लाइसेंस जारी किया जाता है। पूर्व में यहां के बार में मारपीट के साथ महिलाओं से अभद्रता की घटनाएं सामने आ चुकी है।

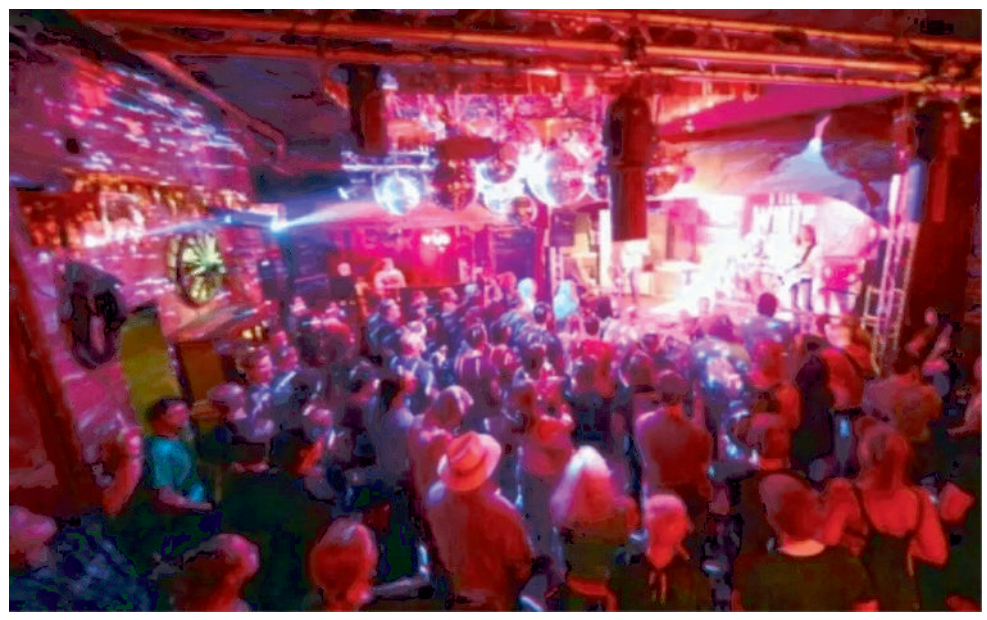

बार में बाउंसर की पिटाई से हो चुकी है एक मौत

बाउंसर की पिटाई से घायल एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। इस कारण लोगों का कहना है कि ऐसी गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों। आबकारी विभाग का कहना है कि पहले भी कई बार को नियमों के उल्लंघन के मामलों में चेतावनी दी है, और इस मामले में भी नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।

प्रशासन ने क्या कहा ?

आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि बार में इस प्रकार की गतिविधियां नियमों के खिलाफ हैं। बार में किसी भी प्रकार से विदेशी युवतियों को नहीं नचाया जा सकता है।

अगर बार प्रबंधन अपने जवाब में यह नहीं स्पष्ट कर पाता है कि यह कार्यक्रम कानूनी अनुमति के तहत आयोजित किया गया था, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरोप सिद्ध होने पर बार के खिलाफ पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

1727 लोगों से वसूले गए 9 लाख रुपये, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती

परिवहन विशेष न्यूज

गुरुग्राम नगर निगम ने शहर में गंदगी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए जून से सितंबर तक 1727 व्यक्तियों पर 9 लाख 62 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। स्वच्छता अभियान के तहत निगरानी दल लगातार शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण कर रहे हैं और गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई कर रहे हैं। निगम गंदगी फैलाने वालों पर सख्त हो गया है।

गुरुग्राम। नगर निगम गुरुग्राम की स्वच्छता टीम शहर में गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई कर रही है। इसके तहत निगम की टीमों ने जून महीने से सितंबर तक गंदगी फैलाने वाले 1727 व्यक्तियों का चालान करके 9 लाख 62 हजार 500 रुपये की अदायगी करवाई है।

जून में गुरुग्राम में ठोस कचरा पर्यावरण आवश्यकता कार्यक्रम (स्वीप) लागू करके कचरा उठान व सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए विशेष अभियान की शुरूआत की गई थी।

अभियान के तहत स्वच्छता टीमों ने सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने के साथ ही ऐसे लोगों पर भी निगरानी शुरू की, जो साफ किए गए स्थानों, सड़कों, गलियों, बाजारों व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कचरा डालकर गंदगी फैलाते हैं।

अकेले जून में 2 लाख से ज्यादा का लगाया जुर्माना

निगरानी के दौरान टीमों ने जून माह में 439 उल्लंघनकर्ताओं पर 2 लाख 22 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुलाई में निगरानी व कार्रवाई को और तेज किया गया तथा गंदगी फैलाने वाले 732 उल्लंघनकर्ताओं पर 4 लाख 18 हजार 500 रुपये जुर्माना लगाया गया।

शहर को गंदा करने वालों पर अगस्त में भी स्वच्छता टीमों ने लगातार निगरानी बनाए रखते हुए 413 व्यक्तियों को मौके पर पकड़ा तथा उनसे 2 लाख 40 हजार 500 रुपये की जुर्माना राशि वसूल की। सितंबर माह में अब तक 143 व्यक्तियों पर 81 हजार 500 रुपये जुर्माना लगाया जा चुका है।

चुनौतियों को चुनौती देकर उन पर विजय हासिल करने वाले को नरेंद्र मोदी कहते हैं

नीरज कुमार दुबे

गुजरात के वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले से लेकर वर्ल्ड स्टेज पर दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शुमार होने तक और एक बार फिर ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में सबसे आगे रहने तक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा बड़ी रोचक और प्रेरणादायक रही है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जन्मदिन पर चारों ओर से बधाइयों का तांता लगा हुआ है। हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए माँ भारती प्रधानमंत्री मोदी को और शक्ति व सामर्थ्य प्रदान करें। वर्ष 1950 में 17 सितंबर के दिन एक साधारण परिवार में जन्मे नरेन्द्र दामोदर दास मोदी का सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना इस बात का संकेत है कि यदि व्यक्ति में दृढ़ इच्छा शक्ति और अपनी मंजिल तक पहुंचने का जज्बा हो, तो वह मुश्किल से मुश्किल हालात को आसान बनाकर अपने लिए नये रास्ते बना सकता है। हम आपको बता दें कि 26 मई 2014 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मोदी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलायी थी। पांच बरस बाद 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर लोकसभा चुनाव जीता और उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की। इस साल नौ जून को उन्होंने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिये प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, जिसके बाद मोदी पंडित जवाहर लाल नेहरू के बाद लगातार तीन बार प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति हो गए हैं। मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री भी हैं जिन्होंने आजाद भारत में जन्म लिया था।

देखा जाये तो देश को आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ाने वाले, देश को गुलामी की मानसिकता से निजात दिलाने वाले, मुश्किल से भी मुश्किल समय में देश को कुशल नेतृत्व देने वाले, बात महामारी की हो या आतंकवाद की...रणनीति और साहस के साथ उनका खात्मा करने वाले, विस्तारवादी ताकतों की सारी हेकड़ी निकालने वाले, देश को अगले 25 सालों के लिए नव-संकल्प दिलाकर सबको साथ लेकर, सबको विश्वास में लेकर आगे बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी के नेतृत्व कौशल की आज पूरी दुनिया कायल है। 'मोदी है तो मुमकिन है', यह कोई महज चुनावी नारा नहीं बल्कि आश्वस्ति का वह भाव है जो देश की जनता के मन में है। देश की जनता सिर्फ इसी बात से निश्चिंत है कि मोदी हैं तो हमारे देश की संप्रभुता और अखण्डता को कोई आंच नहीं आ सकती। जनता बार-बार देख चुकी है कि 'कोई भारत को छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं' यह बात सिर्फ मोदी कहते भर नहीं हैं इसे समय-समय पर हकीकत भी बना कर दिखाते हैं।

गुजरात के वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले से लेकर वर्ल्ड स्टेज पर दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शुमार होने तक और एक बार फिर ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में सबसे आगे रहने तक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा बड़ी रोचक और प्रेरणादायक रही है। नरेंद्र मोदी इस मामले में पहले प्रधानमंत्री हैं जिसने गरीबी को सबसे करीब से देखा है। जिसकी माँ दूसरों के घरों में काम करती हो, जिसने खुद कभी रेलवे स्टेशन पर चाय बेची हो, जिसने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा दो जोड़ी कपड़ों में गुजारा हो, जिसने हिमालय की चोटियों पर बरसों संन्यासी के रूप में गुजारे हों, जिसने मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात को ऐसा चमकाया हो कि दुनिया भारत के इस राज्य की चकाचौंध से जुड़ने के लिए खुद आतुर हुई हो, जिसने प्रधानमंत्री के रूप में भारत को गरीबी और निराशा की स्थिति से निकाला हो और जो देश को एकजुट कर 'नये भारत' और 'विकसित भारत' की परिकल्पना साकार करने के लिए निकल पड़ा हो, उस हस्ती का देश-दुनिया वंदन कर रही है। वाकई ऐसे जुझारू, कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ, भारत की संस्कृति के प्रचारक और राष्ट्रभक्त जनसेवक बिरले ही होते हैं। अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू-कश्मीर से आतंकवाद की लगभग समाप्ति कर कश्मीरी युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने की बात हो या फिर पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद और कुछ राज्यों में आधार रखने वाले माओवाद पर काबू पाने की बात हो, मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में पूर्णतः शांति बनी हुई है और हर जगह सिर्फ कानून का राज है।

नरेंद्र मोदी को जनप्रतिनिधि के रूप में विभिन्न पदों पर रहते हुए 21 साल से ज्यादा समय हो चुका है लेकिन देखिये उनके पास अन्य नेताओं की तरह ना तो आलीशान बंगला है, ना ही बड़े-बड़े बैंक बैलेंस हैं और ना ही चमचमाती कारें हैं। हाँ, उनके पास भारत की जनता का प्यार जरूर है तभी तो चुनावों के समय जनता खुद ही नारा लगाती है- 'नमो नमो', 'मोदी मोदी', 'मोदी है तो मुमकिन है', 'हर हर मोदी घर घर मोदी' लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने देश को जो बड़े नारे या फिर कहिये सूत्रवाक्य दिये वह हैं- 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत', 'सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास'। नरेंद्र मोदी ने अपने लिए बड़ा घर बनाने की जगह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रिकॉर्ड संख्या में जरूरतमंदों के सिर पर छत प्रदान की। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र या अपने गृहराज्य की चिंता करने की बजाय देश को समान रूप से विकास की ऐसी ढेरों परियोजनाएं प्रदान कीं जिससे नये भारत का निर्माण चारों ओर होता दिख रहा है।

भारत का पहला वॉर मेमोरियल, सेंट्रल विस्टा परियोजना, नया संसद भवन, नये संसद भवन में हमारा सेंगोल, भारत मंडपम, यशोभूमि आदि राष्ट्र इमारतें मोदी के कार्यकाल में ही साकार हुईं। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, स्वच्छ भारत, जीएसटी, वन रैंक वन पेंशन, सीडीएस, स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया अभियान, नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति और जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के वादे भारत में बरसों से सुने जाते थे लेकिन यह सब साकार मोदी सरकार के कार्यकाल में ही हुए। यही वह सरकार है जिसने उद्योगों को मजबूती प्रदान करने के लिए तमाम कदम उठाये, उद्योगों की स्थापना संबंधी प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया, मंजूरियां प्रदान करने की प्रक्रिया को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया, युवाओं को रोजगार पाने की जद्दोजहद में जुटने की बजाय उन्हें रोजगार प्रदान करने लायक स्थिति में पहुँचाने के लिए तमाम योजनाओं को पेश किया, कोरोना के कहर से देश को बचाने के लिए भारत में वैक्सीन के निर्माण को प्रोत्साहित भी किया तथा दुनिया में सबसे ज्यादा और तीव्र गति से वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया, संकट के समय महीनों तक गरीब जनता को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया। यही नहीं ओलम्पिक, पैरालम्पिक और राष्ट्रमंडल खेलों के सभी पदक विजेताओं और प्रतिभागी खिलाड़ियों का हौसला प्रधानमंत्री ने निजी रूप से बढ़ाया। विभिन्न क्षेत्रों में मुकाम हासिल करने वालों से बात कर उनका हौसला बढ़ाने की बात हो, युवाओं का विभिन्न अवसरों पर मार्गदर्शन करने की बात हो, छात्रों से परीक्षा पर चर्चा कर उनका हौसला बढ़ाने की बात हो...नरेंद्र मोदी से पहले किसी प्रधानमंत्री ने यह काम नहीं किया।

भोलेनाथ के भक्त और काशी के जनसेवक मोदी ने रामनगरी अयोध्या में श्रीराम का दिव्य और भव्य मंदिर बनवा कर हिन्दुस्तान की जनता का सैंकड़ों वर्षों पुराना सपना साकार कर दिया तो मोदी सरकार के कार्यकाल में ही अल्पसंख्यक मंत्रालय ने मुस्लिमों के लिए इतनी योजनाएं पेश कीं कि आज यह वर्ग पहले की अपेक्षा ज्यादा पढ़ा-लिखा और संपन्न नजर आ रहा है। मोदी ने इस देश में बरसों से चल रही तुष्टिकरण की राजनीति को तो समाप्त किया ही मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक के अभिशाप से भी मुक्ति दिलाई। आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन हो या फिर रक्षा बंधन या भैया दूज का त्योहार, मुस्लिम महिलाएं मोदी को भाई के रूप में राखी भेजती हैं, तिलक भेजती हैं। प्रधानमंत्री स्वयं कई बार अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबुद्ध लोगों से बात कर उनकी समस्याएं हल करने की दिशा में कदम उठा चुके हैं। यही कारण है कि देश में लोकसभा और विधानसभा की कई ऐसी सीटें हैं जो अल्पसंख्यक बहुल होने के बावजूद भाजपा के पास हैं। यह दर्शाता है कि मुस्लिमों को वोट बैंक के रूप में देखने वालों के दिन अब लद चुके हैं।

इस देश में दलितों और पिछड़ों को भी सिर्फ वोट बैंक के रूप में देखा जाता था लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से उनकी सामाजिक और आर्थिक दशा में बड़े बदलाव आये हैं। सबको याद होगा कि प्रयागराज के कुंभ मेले में स्वच्छता कर्मियों के पैर खुद प्रधानमंत्री ने धोये थे और उन्हें सम्मानित किया था। कोई भी परियोजना साकार हो, मोदी उसमें लगे श्रमिकों का सम्मान करना कभी नहीं भूलते। कारीगरों और मजदूरों का काम पहले निर्माण के बाद खत्म समझा जाता था लेकिन मोदी के कार्यकाल में इन श्रमिकों को सम्मान मिल रहा है। यही नहीं, आज पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने का काम जितना नरेंद्र मोदी ने किया है उतना आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। गांवों और किसानों की चिंता करते हुए प्रधानमंत्री ने उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए ना सिर्फ अनेकों योजनाएं पेश कीं बल्कि उनके क्रियान्वयन पर खुद निगाह भी रखी। गरीब किसानों की मदद के वादे तो पहले भी किये जाते थे लेकिन नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान योजना के जरिये ना सिर्फ उनकी आर्थिक मदद की बल्कि तमाम तरह की फसलों का एमएसपी समय-समय पर बढ़ाकर उन्हें और सशक्त भी किया।

मोदी भ्रष्टाचार, परिवारवाद जैसी बुराई का कचरा तो साफ कर ही रहे हैं साथ ही वह स्वच्छ भारत के लिए कितने गंभीर रहते हैं यह देश कई बार देख चुका है। गंदगी दिखे तो झाड़ू लगा देना, समुद्र तट पर जायें तो कचरा एकत्र कर उसे डस्टबिन में डालना और किसी परियोजना के उद्घाटन के समय सिर्फ रिब्बन ही नहीं काटना बल्कि कचरा दिखे तो उसे भी उठा देना...ऐसा सिर्फ आज तक एक ही प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है। प्रधानमंत्री योग से निरोग रहने का संदेश ही नहीं देते उसे खुद भी जीवन में अपनाते हैं। सेना के किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो सैन्य वर्दी को शान से पहनते हैं। मोदी से पहले किसी अन्य प्रधानमंत्री ने जनता से मन की बात अगर की थी तो सिर्फ चुनावों के समय की थी लेकिन मोदी हर महीने के अंत में रेडियो के माध्यम से अपने मन की बात रखते हैं। यही कारण है कि मोदी के मन से वाकिफ जनता उनके एक आह्वान पर उठ खड़ी होती है। मोदी ने कोरोना काल में जो-जो आह्वान किये देश की जनता उनसे जुड़ी, आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर मोदी ने 'हर घर तिरंगा' अभियान का आह्वान किया तो देश के प्रत्येक नागरिक ने मिलकर उसे सफल बनाया।

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV
Drive the Future

इलेक्ट्रिक कम्यूटर बाइक रिवॉल्ट RV1 हुई लॉन्च, 160 KM देगी रेंज, 90 मिनट में होगी फुल चार्ज

परिवहन विशेष न्यूज

इलेक्ट्रिक कम्यूटर बाइक Revolt RV1 को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। इसे दो वेरिएंट RV1 और RV1+ में लेकर आया गया है दोनों की कीमत क्रमश 84990 रुपये और 99990 रुपये है। इसे दो बैटरी ऑप्शन में लाया गया है। जिसमें से एक 2.2 kWh बैटरी और 3.24 kWh बैटरी दी गई है। ये दोनों बैटरी क्रमश 100 किमी और 160 किमी की रेंज देगी।

नई दिल्ली। भारतीय इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी रिवोल्ट मोटर्स ने अपनी दूसरी इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च की है। इस बाइक का नाम Revolt RV1 है। इसे दो वेरिएंट RV1 और RV1+ में लॉन्च किया गया है। भारत में Revolt की इलेक्ट्रिक बाइक का मुकाबला ओला रोडर एक्स से होगा। आइए जानते हैं कि Revolt RV1 को किन फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है और इसकी कीमत कितनी है।

Revolt RV1: कीमत

RV1 और इसके प्रीमियम वैरिएंट को चार कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। Revolt RV को एक्स-शोरूम कीमत 84,990 रुपये में लॉन्च की है और वहीं, RV1+ को 99,990 रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया है। यह लॉन्च रिवोल्ट मोटर्स के प्रीमियम इलेक्ट्रिक लाइनअप और भी बेहतर बनाएगा, जिसमें RV400 और RV400 BRZ जैसे पॉपुलर मॉडल शामिल है।

Revolt RV1: फीचर्स

इसमें 6-इंच डिजिटल एलसीडी डिस्प्ले दी गई है। इसके साथ ही इसमें स्टाइलिश एलईडी हैडलाइट्स और टेल लाइट्स दी गई है। दोनों वेरिएंट में बिल्ट-इन चार्जर स्टोरेज दी गई है। इसमें डुअल डिस्क ब्रेक दी गई है तो आमतौर पर अन्य कम्यूटर मोटरसाइकिलों में नहीं पाई जाती है। बाइक में कई स्पीड मोड भी दिए गए हैं, जिसमें से एक रिवर्स मोड दिया गया है। इससे पार्किंग में आसानी होगी। बाइक में चौड़े टायर दिए गए हैं, जिससे बाइक ज्यादा स्थिर रहेगी।

Revolt RV1: बैटरी

यह मिड-मोटर और चेन ड्राइव सिस्टम पर बेस्ड है। इसमें दो बैटरी ऑप्शन दी है, एक 2.2 kWh बैटरी है जो 100 किमी की रेंज देती है। वहीं, दूसरी बैटरी 3.24 kWh की है, जो 160 किमी की रेंज देती है। कंपनी दावा कर रही है कि दोनों बैटरी ऑप्शन वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP67-रेटेड दी गई है। बाइक फास्ट-चार्जिंग तकनीक के साथ आती है, जिससे बाइक की बैटरी महज 1.5 घंटे में पूरी तरह से चार्ज हो जाती है।

Revolt RV400: अपग्रेड

कंपनी ने RV1 के लॉन्चिंग के दौरान RV400 के अपग्रेड की घोषणा की। यह फास्ट चार्जर के साथ आएगी, जो केवल 90 मिनट में पूरी तरह से चार्ज हो जाएगी, जबकि रिवर्स मोड के फीचर्स से बाइक को पार्क करना आसान हो जाएगा। इसमें बेहतर डिजिटल डिस्प्ले, आरामदायक सीट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, बिल्ट-इन लेग गार्ड, सेंटर स्टैंड जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें 160 किलोमीटर की एक्सटेंडेड रेंज भी दी गई है।

स्टैटिक ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईवी चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर

परिवहन विशेष न्यूज

ग्रेटर नोएडा के पास जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देश की जानी-मानी कंपनी स्टैटिक जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा ईवी चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करेगी। इसको लेकर स्टैटिक कंपनी और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने मंगलवार, 17 सितंबर को भारत की अग्रणी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग नेटवर्क कंपनी स्टैटिक के साथ एक व्यापक एयरसाइड ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। स्टैटिक 24x7 संचालन के लिए एयरसाइड इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना, संचालन और रखरखाव करेगा। सभी रियायतकर्ता और हवाई अड्डे के वाहनों को इस मजबूत ईवी चार्जिंग नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त होगी, जिसे हवाई अड्डे की स्थिरता पहलों का समर्थन करने और इसके संचालन में उत्सर्जन को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

स्टैटिक ने ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए कंपनी के साथ साझेदारी की है जो हवाई अड्डे के भीतर इलेक्ट्रिक ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट और अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों की तैनाती की अनुमति देगा। इस साझेदारी के पहले चरण में स्टैटिक छोटे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 7.4 किलोवाट एसी चार्जर और उच्च-शक्ति, तेज़ चार्जिंग आवश्यकताओं के लिए 120 किलोवाट और 240 किलोवाट चार्जर का एक नेटवर्क स्थापित करेगा।

इस अवसर पर टिप्पणी करते हुए, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मुख्य विकास अधिकारी निकोलस शेंक ने कहा, ₹हम भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग नेटवर्क में से एक, स्टैटिक के साथ साझेदारी करके बहुत खुश हैं। स्टैटिक की विशेषज्ञता के साथ, हम एयरसाइड संचालन के लिए 24×7 फास्ट ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

स्टैटिक कंपनी के संस्थापक और सीटीओ राघव अरोड़ा ने कहा, ₹हम एयरसाइड संचालन को विद्युतीकृत करने की इस परिवर्तनकारी यात्रा में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ साझेदारी करके रोमांचित हैं। हमारे प्रगतिशील और अभिनव चार्जिंग समाधान निर्बाध, कुशल और टिकाऊ गतिशीलता सुनिश्चित करेंगे, जो नवाचार और पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारी साझा प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाएगा।"

उन्होंने कहा कि स्टैटिक कंपनी की उन्नत चार्जिंग तकनीक हवाई अड्डे के महत्वाकांक्षी संधारणीयता लक्ष्यों का समर्थन करेगी, जिससे भारत के विमानन क्षेत्र में हरित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने में मदद मिलेगी।

एक देश बना इलेक्ट्रिक कारों का गढ़

परिवहन विशेष न्यूज

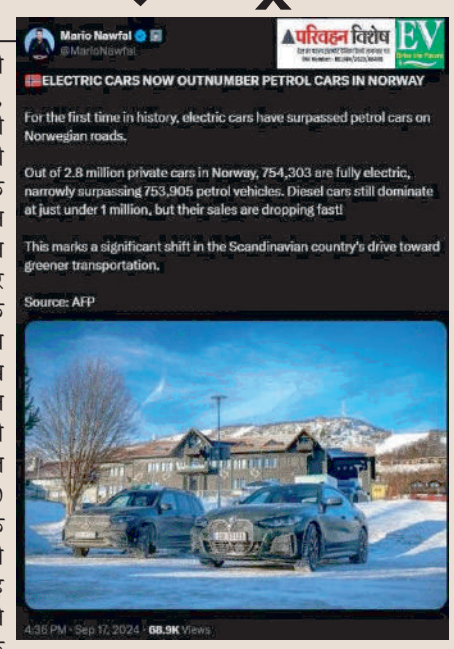

नॉर्वे ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, सड़कों पर पेट्रोल वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक कारों की संख्या अधिक है। नॉर्वे के रोड ट्रैफिक इंफॉर्मेशन का उं सि ल (ओप्लिसिंगस्राडेट फॉर वीट्राफिकेन, OFV) के डेटा का विश्लेषण किया गया और नॉर्वे के प्रमुख ऑटो उद्योग प्रकाशन बिलब्रांसजे 24 द्वारा जारी किया गया। अगस्त के अंत तक नॉर्वे में 7,51,450 इलेक्ट्रिक वाहन थे, जबकि पेट्रोल-आधारित कारों की संख्या 7,55,244 थी। यह उपलब्धि नॉर्वे की पिछले कुछ वर्षों की रणनीतिक नीतियों और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की उच्च दरों का परिणाम है। नॉर्वे ने बड़े सरकारी प्रोत्साहनों, कर छूट और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के माध्यम से यह बदलाव किया है, जो टिकाऊ परिवहन समाधानों की ओर बढ़ रहा है।

आंकड़ों के अनुसार नॉर्वे की सड़कों पर कुल वाहनों में से अब लगभग 26% ईवी हैं, जो पिछले वर्षों की तुलना में बहुत बड़ी वृद्धि है। अकेले अगस्त के महीने में नॉर्वे में नई कार की बिक्री में 94% इलेक्ट्रिक वाहन थे, एक नया विश्व रिकॉर्ड और नॉर्वे को इलेक्ट्रिक वाहन बाजार हिस्सेदारी में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना। यह उच्च ईवी बिक्री दर नॉर्वे की जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 2025 तक पेट्रोल कारों की बिक्री को रोकने का नॉर्वे का महत्वाकांक्षी लक्ष्य पहले ही तय समय से पहले पूरा हो गया है। 2021 तक गैर-विद्युतीकृत वाहनों की बिक्री बहुत कम स्तर पर आ गई थी। नॉर्वे की इस सक्रिय नीति ने इसे अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत पहले इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में अग्रणी बना दिया है।

नॉर्वे की सड़कों पर डीजल वाहन अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2014 के अंत में डीजल कारों की संख्या पेट्रोल कारों से अधिक थी और तब से यह बढ़त बरकरार है। हालांकि, डीजल वाहनों की संख्या में भी कमी आ रही है और उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक यह संख्या एक मिलियन से नीचे आ जाएगी। नॉर्वे में इलेक्ट्रिक और डीजल वाहनों के साथ-साथ हाइब्रिड मॉडल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में नॉर्वे की सड़कों पर लगभग 2,08,000 प्लग-इन हाइब्रिड और 1,56,000 नॉन-प्लग-इन हाइब्रिड वाहन हैं। 2019 से प्लग-इन हाइब्रिड की संख्या नॉन-प्लग-इन हाइब्रिड से अधिक हो गई है, जो अधिक पर्यावरण के अनुकूल वाहनों की ओर बदलाव को दर्शाता है।

डीजल और पेट्रोल कारों की घटती संख्या ने नॉर्वे में मोटर ईंधन की बिक्री को भी प्रभावित किया है। जीवाश्म ईंधन वाहनों की घटती मांग और इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण पेट्रोल और डीजल की मांग में उल्लेखनीय गिरावट आई है। 6 मिलियन से कम आबादी वाला और तेल, गैस, जलविद्युत, मछली, जंगल और खनिजों जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध एक छोटा स्कैंडिनेवियाई देश नॉर्वे ने यह सफलता हासिल की है।

क्लाइमेट प्लेज ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहन के लिए लॉन्च किया साझा चार्जिंग स्टेशनों का नया नेटवर्क

परिवहन विशेष न्यूज

क्लाइमेट प्लेज ने आज अपने हस्ताक्षरकर्ताओं और उद्योग भागीदारों के साथ भारत के बेंगलुरु शहर में साझा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशनों का एक नया नेटवर्क बनाने के लिए एक नई संयुक्त पहल – जेओयूएलई (जॉइंट ऑपरेशन यूनिफाइंग लास्ट-माइल इलेक्ट्रिफिकेशन) की घोषणा की। अमेज़न और ग्लोबल ऑप्टिमिज़्म द्वारा 2019 में सह-स्थापित, क्लाइमेट प्लेज पेरिस समझौते में तय 2040 के लक्ष्य के मुकाबले 10 साल पहले साल पहले नेट-ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

क्लाइमेट प्लेज के हस्ताक्षरकर्ता और भागीदार सामूहिक रूप से 2030 तक इस परियोजना में 2.65 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश करेंगे। अमेज़न, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, उबर, एचसीएलटेक और मैजेंटा मोबिलिटी ईवी चार्जिंग स्टेशनों के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए मिलकर काम करेंगे, अपने ईवी बेड़े की चार्जिंग आवश्यकताओं को मिलाकर यह सुनिश्चित करेंगे कि बुनियादी ढांचे का अच्छी तरह से उपयोग किया जाए। उद्योग भागीदार और भारतीय ईवी चार्जिंग प्लेटफॉर्म, काज़म साझा चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क बनाएगी। इस परियोजना को नवीकरणीय ऊर्जा प्रदाता ग्रीनको और रणनीतिक परामर्श भागीदार डेलॉइट भी समर्थन करेगी।

क्लाइमेट प्लेज की ग्लोबल लीडर, सैली फाउट्स ने कहा, ₹हमें क्लाइमेट प्लेज हस्ताक्षरकर्ताओं के साथ यह संयुक्त पहल शुरू करने पर गर्व है जो भारत के इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलाव का समर्थन करेगी, जिसमें 2030 तक तिपहिया वाहन, कैब सेवा और कॉर्पोरेट बेड़े को 100% ईवी में परिणत करने का बेंगलुरु का लक्ष्य भी शामिल है। यह परियोजना न केवल भारत के चार्जिंग बुनियादी ढांचे की कुछ मौजूदा चुनौतियों का समाधान करती है ताकि अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन अपनाए जा सकें, बल्कि कॉर्पोरेट जलवायु सहयोग के लिए एक नया मानक भी स्थापित करती है।"

इस परियोजना के तौर पर डोड्डकल्लसांद्रा में स्थित पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन आज से पूरी तरह चालू है और इस परियोजना का लक्ष्य है, इस साल के अंत तक बेंगलुरु में पांच और चार्जिंग स्टेशन बनाना और स्थानीय ईवी बुनियादी ढांचे की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आगे विस्तार की योजना है। परियोजना से 2030 तक बेंगलुरु में लगभग 5,500 ईवी का समर्थन कर पाने का अनुमान है (अपेक्षित मांग के आधार पर), यह पूरी क्षमता पर लगभग 9,500 ईवी की सेवा करने में सक्षम है। उपयोग को अधिकतम करने के लिए, अन्य कंपनियों के लिए दिन के दौरान अपने बेड़े के वाहनों को चार्ज करने के लिए

बुनियादी ढांचा भी उपलब्ध होगा।

चार्जिंग स्टेशनों द्वारा उपयोग की जाने वाली सारी बिजली (जो 22,700 मेगावाट-घंटे के स्तर पर पहुंचने का अनुमान है) की 100% भरपाई नवीकरणीय ऊर्जा से होगी, जो 2030 तक अनुमानित 6.2 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के बराबर होगी। उसी साल तक, इस परियोजना से 11.2 मिलियन लीटर से अधिक ईंधन की बचत होने और अनुमानित तौर पर 25,700 टन कार्बन-डाइऑक्साइड में कमी होने की भी उम्मीद है। टेल पाइप उत्सर्जन को कम करने के अलावा, यह परियोजना 2024 से 2030 के बीच बेंगलुरु में अनुमानित 185 पूर्णकालिक नौकरी का सृजन करेगी।

कर्नाटक सरकार में उद्योग आयुक्त, भारतीय प्रशासनिक सेवा के गुंजन कृष्णा ने कहा, ₹बेंगलुरु में ईवी चार्जिंग स्टेशनों का एक साझा नेटवर्क स्थापित करना, इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देने के हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, और हम क्लाइमेट प्लेज के नेतृत्व में इस नवोन्मेषी सहयोग का पूर्ण समर्थन करते हैं। यह पहल न केवल ईवी बुनियादी ढांचे की पहुंच को बढ़ाती है, बल्कि भारत के अपेक्षाकृत अधिक वहनीय भविष्य की ओर बढ़ने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की शक्ति भी प्रदर्शित करती है।"

डेलॉइट के नए श्वेतपत्र के अनुसार, भारत को 2030 तक सभी नए वाहनों की बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी 30% करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, देश को प्रति 20 वाहनों पर 1 चार्जिंग स्टेशन की आवश्यकता होगी। मौजूदा अनुपात - लगभग 135 ईवी पर 1 चार्जिंग स्टेशन - इससे काफी कम है और देश के ईवी में बदलाव में बाधा डालता है। ईवी चार्जिंग स्टेशनों की कमी, उपयोग दरों में अनिश्चितता, रेंज की चिंता, ऊंची पूंजी लागत और लाभों के बारे में जागरूकता की कमी के कारण व्यवसायों द्वारा चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने में हिचकिचाहट जैसी प्रमुख चुनौतियां संभावित ईवी मालिकों के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं।

संयुक्त सहयोग परियोजना समर्पित चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर इन चुनौतियों का समाधान करती है जो कॉर्पोरेट उपभोक्ताओं के लिए प्राथमिकता वाली पहुंच, सुरक्षा सेवा, आवश्यक सुविधा और समर्पित पार्किंग स्लॉट प्रदान करते हैं। मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों की कंपनियों को साथ लाकर और उपयोग की मांग को इकट्ठा (एग्रीगेट) कर, परियोजना बुनियादी ढांचे की उपयोग दर और वित्तीय व्यवहार्यता पर अधिक निश्चितता भी प्रदान करती है।

डेलॉयट साउथ एशिया के पार्टनर, क्लाइमेट चेंज एवं सस्टेनेबिलिटी लीडर, शैलेश त्यागी ने कहा, ₹भारत का सड़क परिवहन क्षेत्र अभी भी डीजल और पेट्रोल पर बहुत अधिक निर्भर है, जिसका प्रदूषण और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर बेहद नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहां एक उम्मीद की किरण है - भारत में ईवी की पहुंच अन्य देशों की तुलना में कम है, लेकिन 2030 तक यह दुनिया के सबसे बड़े ईवी बाज़ारों में से एक बन जाने की उम्मीद है। विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों को एक साथ लाकर, यह पहल ईवी चार्जिंग के लिए एक अधिक टिकाऊ और कुशल मॉडल बनाने में मदद कर रही है - और भारत में ईवी अपनाने में तेज़ी ला रही है।₹

काज़म के सीओओ और सह-संस्थापक, पारस शाह ने कहा, ₹काज़म को ई-कॉमर्स और इलेक्ट्रिक फ्लीट ऑपरेटरों के लिए तैयार किए गए हमारे उन्नत ईवी चार्जिंग समाधानों के ज़रिये क्लाइमेट प्लेज और इसके हस्ताक्षरकर्ताओं का समर्थन करने पर गर्व है। हमें जेओयूएलई परियोजना में अपनी भागीदारी की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, जो स्वच्छ और अधिक टिकाऊ भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। काज़म में, हमारा मानना है कि जेओयूएलई परियोजना, जलवायु परिवर्तन से निपटने और ग्रीन मोबिलिटी में बदलाव को आगे बढ़ाने के हमारे साझा मिशन की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है।"

पिछले साल, क्लाइमेट प्लेज ने लेनशिफ्ट पहल की घोषणा की थी जिसके तहत भारत और लैटिन अमेरिका के प्रमुख शहरों में शून्य-उत्सर्जन वाले इलेक्ट्रिक ट्रकों और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और तैनाती को गति देने के लिए सी40 शहरों को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने के प्रति प्रतिबद्धता जताई गई थी। भारत में, लेनशिफ्ट मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली और पुणे में ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और ईवी वाहनों की तैनाती में तेज़ी लाएगा, जिससे उत्सर्जन कम करने, हवा साफ करने और नए रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी।

टाटा मोटर्स और जेएलआर मिलकर भारत में बनाएंगे इलेक्ट्रिक वाहन और दुनिया भर में करेंगे निर्यात : एन चंद्रशेखरन

परिवहन विशेष न्यूज

टाटा मोटर्स और जगुआर लैंड रोवर अब वैश्विक बाजार के लिए भारत में इलेक्ट्रिक वाहन का निर्माण करेंगे। टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने हाल ही में एक मीडिया साक्षात्कार में यह जानकारी दी हैं।

ऑटोकार को दिए एक साक्षात्कार में चंद्रशेखरन ने कहा कि टाटा मोटर्स और जेएलआर कई वर्षों से इस क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं और अब भारत में वैश्विक बाजारों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण की योजना को अंतिम रूप दिया गया है।

जेएलआर के इलेक्ट्रिफाइड मॉड्यूलर आर्किटेक्चर (ईएमए) प्लेटफॉर्म का जिक्र करते हुए चंद्रशेखरन ने यह भी कहा कि इस प्लेटफॉर्म के भारत में दो अलग-अलग मॉडल होंगे, एक जेएलआर के लिए और दूसरा टाटा मोटर्स के लिए।

उन्होंने कहा, "हम साणंद से जेएलआर कारों का निर्यात भी करेंगे।" विस्तृत जानकारी दिए बिना चंद्रशेखरन ने कहा कि उनकी "बड़ी आकांक्षाएं" हैं और टाटा मोटर्स अगले 12 महीनों में अपनी निर्यात योजनाओं पर चर्चा करेगी।

गुजरात के साणंद स्थित प्लांट में ईएमए प्लेटफॉर्म पर आधारित पहली कार बनने की संभावना है, जिसे अविन्या के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है कि इस कार का निर्माण वैश्विक बाजार के लिए किया जाएगा, साथ ही इसे भारत में भी बेचा जाएगा। टाटा मोटर्स ने साणंद स्थित अमेरिकी वाहन निर्माता कंपनी फोर्ड मोटर्स के पुराने प्लांट का भी अधिग्रहण कर लिया है।

जेएलआर के पास पहले से ही यूनाइटेड किंगडम, चीन, यूरोप और अन्य स्थानों पर विनिर्माण संयंत्र हैं और इसने अपनी विद्युतीकरण योजना की रूपरेखा तैयार की है। टाटा मोटर्स ने अपनी वित्त वर्ष 2024 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि नई ईएमए और जगुआर इलेक्ट्रिफाइड आर्किटेक्चर को 2025 से पेश किया जाएगा क्योंकि यह पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्यवसाय की ओर बढ़ रहा है, इसके सभी ब्रांड 2030 तक शुद्ध इलेक्ट्रिक विकल्प पेश करेंगे।

जेएलआर की विद्युतीकरण योजना के हिस्से के रूप में, दुनिया भर में इसके विनिर्माण संयंत्रों को भी ईवी उत्पादन का समर्थन करने के लिए संशोधित और अद्यतन किया जाएगा। इलेक्ट्रिक जगुआर का उत्पादन सोलीहुल में किया जाएगा, इसके बाद यूनाइटेड किंगडम के मर्सीसाइड में हेलवुड का उत्पादन किया जाएगा, जिसे पहले 'इलेक्ट्रिक विनिर्माण संयंत्र' में परिवर्तित किया जाएगा। स्लोवाकिया के नित्रा में जेएलआर के संयंत्र को 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन करने के लिए अपडेट किया जाएगा।

जेएलआर वित्त वर्ष 2020 की आधार रेखा की तुलना में 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की दिशा में काम कर रही है। कंपनी अपने भागीदारों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ मिलकर अपने परिचालन में 46 प्रतिशत और अपनी पूरी मूल्य श्रृंखला में प्रति वाहन 54 प्रतिशत उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य रखती है।

अपने साक्षात्कार में चंद्रशेखरन ने नई संभावनाओं का पता लगाने के लिए खुले विचारों और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा, ₹हम टाटा मोटर्स के लागत-केंद्रित दृष्टिकोण को जेएलआर के डिजाइन के साथ जोड़ सकते हैं। अगर हम ऐसा कर सकते हैं, तो हम एक आदर्श स्थिति में होंगे। तब आपको दो अलग-अलग तरीकों से लाभ मिलेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा, जो ईएमए प्लेटफॉर्म में निवेश को सही ठहराएगा।"

उन्होंने कहा कि टाटा मोटर्स के लिए अकेले यह निवेश करना संभव नहीं हो सकता है और जेएलआर का कारोबार शायद पर्याप्त न हो। उन्होंने कहा, ₹हम सिर्फ़ प्लेटफॉर्म के बारे में ही बात नहीं कर रहे हैं बल्कि इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर के बारे में भी बात कर रहे हैं।"

साणंद प्लांट के अलावा विनिर्माण और निर्यात के लिए एक और प्रमुख केंद्र तमिलनाडु की आगामी परियोजना हो सकती है। इस नई परियोजना में 9,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है और यह टाटा मोटर्स और जेएलआर का संयुक्त प्लांट हो सकता है। इस महीने के अंत में इसकी घोषणा की जा सकती है।

टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने इस दशक के अंत तक इलेक्ट्रिक वाहनों में कई अरब डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है, जबकि जेएलआर ने अगले पांच वर्षों में 15 अरब पाउंड से अधिक पूंजीगत व्यय का रोडमैप तैयार किया है।

चंद्रशेखरन ने कहा कि उन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में किसी भी अल्पकालिक मंदी की चिंता नहीं है और उन्होंने इसे एक चक्रीय प्रक्रिया बताया। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मामले में वित्त वर्ष 2025 टाटा मोटर्स के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में टाटा मोटर्स के कुल यात्री वाहनों की थोक बिक्री में 1.1 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री (16,600 यूनिट) में 13.9 प्रतिशत की तीव्र गिरावट आई, जिसकी वजह फ्लीट सेगमेंट में तेज गिरावट रही।

उन्होंने कहा, "अगर हमें भारत में कुछ करना है, तो इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि हमारे पास दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की संख्या सबसे ज्यादा है। टॉप 20 में से 14 शहर भारत में हैं। इसलिए, अगर हमें इस समस्या का समाधान करना है, तो हमें अपनी सभी कंपनियों में इस दिशा में आगे बढ़ना होगा।"

खेल, एथलेटिक्स और शारीरिक फिटनेस में करियर के अवसर

विजय गर्ग

वे दिन गए जब खेल और एथलेटिक्स को एक मनोरंजक गतिविधि या बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पैदा किया जाने वाला शौक माना जाता था। लोग केवल मनोरंजन के लिए या अधिक से अधिक उस क्षेत्र के गौरव के लिए खेल खेलते थे जिसका वे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिनिधित्व करते हैं। वे पेशेवर गतिविधि के बजाय खेल खेलना पसंद करते हैं। किसी विशेष खेल को अपनाते समय उन्होंने न तो बड़ी पुरस्कार राशि के रूप में धन कमाने के बारे में सोचा और न ही इससे करियर बनाने के बारे में। एस वेंकट राघवन, जेफरी बायकॉट, चैपल ब्रदर्स (इयान और ग्रेग), सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, हर्षा भोगला ऐसे नाम हैं जो अभी भी सक्रिय वर्तमान और पूर्व खिलाड़ियों की एक लंबी सूची में से हैं, जिन्होंने न केवल अपने लिए एक सम्मानजनक जगह बनाई है। न केवल खेल गतिविधियों में उनकी भागीदारी ने भारत और विदेशों में सबसे आकर्षक विकल्पों में से एक के रूप में खेल में करियर बनाने में भी भूमिका निभाई। हालाँकि भारत और अधिकांश अन्य टेस्ट खेलने वाले देशों में क्रिकेट को किसी से कम नहीं माना जाता है, लेकिन इसकी लोकप्रियता के मामले में, रोनाल्डो, काका, टाइगर वुड्स, गीत सेठी, लिएंडर पीज़, वरिंदर सिंह और कई अन्य लोग अभी भी मौजूद हैं जिन्होंने इसके प्रति रुझान विकसित किया है। खेलों के अन्य रूपों की ओर भी, मुख्य रूप से मुक्केबाजी, टेनिस, फुटबॉल और हॉकी। इसके परिणामस्वरूप खेल भारत में चुने हुए करियर विकल्पों में से एक बन गया है। विभिन्न प्रकार की खेल गतिविधियों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशेष रूप से समर्पित अधिक से अधिक अकादमियाँ आ रही हैं। भारत में, भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) सर्वोच्च निकाय है जिसे युवा प्रतिभाओं को खेलों में रुचि विकसित करने और उनकी चुनी हुई खेल गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी दी गई है। SAI के तहत कार्यरत सरकारी और निजी अकादमियाँ विभिन्न खेल गतिविधियों में औपचारिक प्रशिक्षण प्रदान करती हैं, ताकि ऐसे खिलाड़ी तैयार किए जा सकें जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकें। यह प्रवृत्ति केवल खेल गतिविधियों तक ही सीमित नहीं है, वास्तव में यही बात एथलेटिक्स और क्षेत्र में अन्य संबंधित आयोजनों पर भी लागू होती है। पढ़ाई के लिए खेल को गौण चीज मानने की पारंपरिक सोच ने इस सोच को जन्म दिया है कि जहां तक जीवन में करियर चुनने का सवाल है तो खेल भी ड्राइविंग सीट पर हो सकता है। बस इसी वजह से कई सरकारी और निजी संचालित खेल और एथलेटिक्स संस्थान जैसे लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (ग्वालियर), एमआरएफ पेस फाउंडेशन (चेन्नई), टाटा फुटबॉल अकादमी (जमशेदपुर), राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (बैंगलोर) और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान (पटियाला) औपचारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारत आए हैं। अभ्यर्थी अपनी

बुनियादी शैक्षणिक योग्यताएं जैसे शारीरिक शिक्षा के साथ 10+2 स्तर/शारीरिक शिक्षा के साथ स्नातक/शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन संस्थानों में शामिल हो सकते हैं। खेलों ने भारत में युवा प्रतिभाओं के लिए करियर के कई अवसर खोले हैं। विभिन्न खेल अकादमियों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद, कोई भी खिलाड़ी के रूप में करियर बनाने का विकल्प चुन सकता है और पहले कॉलेज, विश्वविद्यालय और राज्य स्तर पर खेल सकता है और फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसरों की तलाश कर सकता है। एक खिलाड़ी के रूप में सेवा करने के अलावा, एक अनुभवी खिलाड़ी कोच, टीम मैनेजर, फिटनेस प्रशिक्षक, अंपायर या रेफरी के रूप में भी काम कर सकता है। इन विकल्पों के अलावा उम्मीदवार एथलेटिक ट्रेनर के रूप में भी अपना करियर बना सकते हैं, जिसे एक संबद्ध स्वास्थ्य पेशा माना जाता है, जिसमें ट्रेनर घायल एथलीटों की चिकित्सा आवश्यकताओं की देखभाल करता है।एक एथलेटिक ट्रेनर का काम एक खिलाड़ी के रूप में क्षेत्र में अर्जित कौशल और ज्ञान का उपयोग करके चोटों को रोकना, उनका निदान करना और सही और तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करना है। एथलेटिक ट्रेनर का महत्व इस तथ्य से मिलता है कि टीम या व्यक्ति की सफलता और सुरक्षा काफी हद तक एक कुशल एथलेटिक ट्रेनर की दक्षता पर निर्भर करती है। आम तौर पर, एथलेटिक प्रशिक्षकों को पेशेवर खिलाड़ियों (व्यक्तियों) या पूरी टीम द्वारा नियुक्त किया जाता है। एक कुशल एथलेटिक प्रशिक्षक घायल खिलाड़ी (खिलाड़ियों) की ताकत वापस लाने के लिए जिम्मेदार होता है। एक एथलेटिक प्रशिक्षक एथलीटों को उपकरणों के सही उपयोग के बारे में मार्गदर्शन करता है और व्यायाम करने के सही तरीके बताता है। यहां तक कि किफायती उपकरण खरीदने का काम भी उसके दायरे में आता है।

वह अभ्यास और प्रतियोगिता में अपनी वापसी का निर्णय लेने के लिए डॉक्टर, प्रशिक्षक और उसके परिवार के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। प्रशिक्षक के लिए प्राथमिक चिकित्सा चिकित्सा उपचार के बारे में जानकारी आवश्यक है। यह भी सर्वविदित तथ्य है कि हर सफल एथलीट के पीछे एक अच्छे एथलेटिक प्रशिक्षक की कड़ी मेहनत और समर्पण होता है। इस प्रकार उसे मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होने की आवश्यकता है, क्योंकि उसे खिलाड़ी को फिट बनाने के लिए अत्यधिक दबाव में लंबे समय तक काम करना पड़ता है, वह भी चुनौतीपूर्ण समय अवधि में। खेल गतिविधियों के प्रति युवा पीढ़ी के रुझान में वृद्धि ने भारत के साथ-साथ विदेशों में भी कुशल और पेशेवर रूप से प्रशिक्षित एथलेटिक प्रशिक्षकों के लिए अवसरों का दायरा बढ़ा दिया है, क्योंकि कोई भी पेशेवर खेल टीमों, औद्योगिक या कॉर्पोरेट में एथलेटिक प्रशिक्षक का कार्य संभाल सकता है। सेटिंग्स. अनुभवी एथलेटिक ट्रेनर स्वास्थ्य शिक्षक या प्रशिक्षण विशेषज्ञ के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। जहां तक वित्तीय पहलू का सवाल है तो खिलाड़ी का पारिश्रमिक पूरी तरह से संबंधित व्यक्ति की चुनी हुई खेल गतिविधि और प्रतिभा पर निर्भर करता है। खेल के क्षेत्र में, केवल क्षेत्र में अनुभव के वर्षों की संख्या ही मायने नहीं रखती, बल्कि खिलाड़ी की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की क्षमता भी मायने रखती है। हालाँकि, किसी भी खेल या एथलेटिक्स में असाधारण खिलाड़ियों के लिए गैर-खेल गतिविधियों जैसे विज्ञापन आदि से भी धन का प्रवाह रुक जाता है, यहाँ तक कि कुछ मामलों में धन का ये गैर-खेल प्रवाह वास्तविक खेल आय से भी अधिक हो सकता है, लेकिन ये सभी तब तक बने रहते हैं जब तक व्यक्ति अपने दायर में प्रदर्शन कर रहा है. खेल के क्षेत्र में असाधारण धन को ध्यान में रखते हुए और कोचिंग, खेल से संबंधित गतिविधियों में प्रबंधकीय नियुक्ति जैसे संबंधित क्षेत्रों में नौकरियों के रूप में खिलाड़ी के करियर के विस्तार ने इसे आज के उभरते युवाओं के बीच वास्तव में पसंदीदा करियर विकल्प बना दिया है। . एक उम्मीदवार इस क्षेत्र में तीन मुख्य विकल्प अपना सकता हैः- आम तौर पर नियोक्ता/प्रमोटर/सरकारी सहायता से प्रायोजन के साथ खेल या गेम को पूर्णकालिक आधार पर आगे बढ़ाएं। किसी खेल या खेल आयोजन के लिए प्रशिक्षक/प्रशिक्षक/प्रशिक्षक बनें। अंततः एक खिलाड़ी के रूप में वर्षों से प्राप्त अनुभव का उपयोग संबंधित क्षेत्र में काम करने के लिए करें, जैसे खेल पत्रकारिता, खेल सामान निर्माण/विपणन या कमेंटेटर के रूप में।

घर पर जेईई मेन 2025 की तैयारी कैसे करें

भारत में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में से एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) मुख्य है, जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश निर्धारित करती है और भारतीय प्रवेश के लिए जेईई एडवांस के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करती है। प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)। जेईई मेन की तैयारी के लिए प्रभावी अध्ययन विधियां, रणनीतिक योजना और प्रतिबद्धता आवश्यक है। ऑनलाइन संसाधनों की पहुंच के कारण बड़ी संख्या में छात्र इस कठिन परीक्षा के लिए घर से अध्ययन करना पसंद कर रहे हैं। परीक्षा संरचना और पाठ्यक्रम को समझना किसी भी तैयारी को शुरू करने से पहले पाठ्यक्रम और परीक्षा संरचना को समझना चाहिए। जेईई मेन में दो पेपर शामिल हैं: पेपर 1 बीई या बीटेक का लक्ष्य रखने वाले आवेदकों के लिए है, जबकि पेपर 2 बी आर्क या बी प्लानिंग करने वालों के लिए है। अधिक व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले पेपर 1 को तीन खंडों में विभाजित किया गया है: गणित, रसायन विज्ञान और भौतिकी, जिनमें से प्रत्येक को समान महत्व दिया गया है। प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के हैं, और गलत उत्तर देने पर नकारात्मक अंक दिया जाएगा। एक सुव्यवस्थित अध्ययन दिनचर्या स्थापित करना और उसका पालन करना महत्वपूर्ण है। जब आप घर से तैयारी कर रहे हों तो समय प्रबंधन और अनुशासन अधिक महत्वपूर्ण हैं। बर्नआउट को रोकने के लिए, एक ठोस अध्ययन कार्यक्रम उचित होना चाहिए और इसमें विराम शामिल होना चाहिए। अध्ययन योजना बनाने की प्रक्रिया 1. दैनिक उद्देश्यः अपने पाठ्यक्रम को सुपाच्य भागों में विभाजित करें और दैनिक लक्ष्य निर्धारित करें। उदाहरण के तौर पर, प्रत्येक विषय के लिए हर दिन विशेष घंटे निर्धारित करें ताकि आप सब कुछ व्यवस्थित तरीके से कवर कर सकें। 2. साप्ताहिक पुनरीक्षणः आपके द्वारा पढ़ी गई सामग्री की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक सप्ताह एक दिन निर्धारित करें।

यह जानकारी बनाए रखने और कमजोर बिंदुओं की पहचान करने में सहायता करता है। 3. मॉक परीक्षाः अपने कैलेंडर में बार-बार मॉक परीक्षा की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। वास्तविक परीक्षा की शर्तों को दोहराने के लिए, इन्हें एक समयबद्ध सेटिंग में पूरा किया जाना चाहिए। आत्म मूल्यांकन और नियमित अभ्यास जेईई मेन पाठ्यक्रम को समझने के लिए, व्यक्ति को लगातार अभ्यास करना चाहिए और स्वयं का मूल्यांकन करना चाहिए। इसमें पिछले वर्षों की अधिक से अधिक अभ्यास परीक्षाओं और प्रश्न पत्रों को पूरा करना शामिल है। अभ्यास तकनीकें: - समयबद्ध अभ्यासः सटीकता और

गति बढ़ाने के लिए, समय की कमी के तहत लगातार अभ्यास करें। - त्रुटि विश्लेषणः अपनी त्रुटियों की जांच करें और प्रत्येक परीक्षण के बाद उनका विश्लेषण करके निर्धारित करें कि आपसे कहां गलती हुई। यह समान गलतियों को दोबारा होने से रोकने में सहायता करता है। - कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान दें: अपनी कमजोरी वाले क्षेत्रों को पहले ही पहचान लें और इन विषयों पर अधिक समय दें। किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए इंटरनेट संसाधनों से परामर्श लें। मजबूत बुनियादी सिद्धांतों का निर्माण याद रखने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, जेईई मेन प्रश्न वैचारिक ज्ञान का आकलन करने के लिए प्रसिद्ध हैं। इसलिए, गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान में ठोस नींव विकसित करना आवश्यक है। वैचारिक स्पष्टता विकसित करने की विधियाँः – एनसीईआरटी पुस्तकें: ये विशेषकर रसायन विज्ञान में बुनियादी समझ के लिए आधार तैयार करने के लिए सर्वोत्तम हैं। अधिक उन्नत सामग्री पर जाने से पहले, सुनिश्चित करें कि आप अपनी एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों के प्रत्येक विचार को समझते हैं। - इंटरएक्टिव लर्निंगः कठिन विषयों को बेहतर ढंग से समझने के लिए, विशेष रूप से भौतिकी में, फिल्मों और सिमुलेशन जैसे दृश्य सहायता का उपयोग करें। - समस्या समाधानः केवल सूत्र याद करने पर निर्भर रहने के बजाय, नियमित रूप से वैचारिक समस्याओं को हल करने का अभ्यास करें। यह आपके ज्ञान को कई सेटिंग्स में लागू करने की सुविधा प्रदान करेगा। प्रवास केप्रेरित और तनाव का प्रबंधन घर पर जेईई मेन के लिए अध्ययन करना मानसिक रूप से थका देने वाला हो सकता है। प्रेरणा बनाए रखना और अच्छे तनाव प्रबंधन का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। - अल्पकालिक लक्ष्य बनाएं: अपनी तैयारी को प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करें, और जब आप उन्हें पूरा कर लें तो स्वयं का ध्यान रखें।

इससे आपको प्रेरित रहने में मदद मिलेगी. इसके परिणामस्वरूप आप निपुण और प्रेरित महसूस करते हैं। - सहकर्मी बातचीतः सामग्री का आदान-प्रदान करने, एक-दूसरे को प्रोत्साहित करने और अपने किसी भी संदेह पर चर्चा करने के लिए ऑनलाइन अध्ययन समूहों में भाग लें। - शारीरिक गतिविधिः अपने शरीर और दिमाग के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, प्रत्येक दिन शारीरिक गतिविधि के लिए समय निकालें। योग और अन्य आसान वर्कआउट तनाव कम करने में मदद कर सकते हैं। परीक्षा तनाव का प्रबंधनः - माइंडफुलनेस तकनीकः आप गहरी सांस लेने और ध्यान जैसी गतिविधियों में संलग्न होकर संयम और ध्यान बनाए रख सकते हैं। – संतुलित आहारः एकाग्रता के स्तर को बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर और संतुलित आहार खाने की आवश्यकता होती है। - नींदः सुनिश्चित करें कि आपको हर रात सात से आठ घंटे का आराम मिले। नींद की कमी से आपके लिए अच्छा काम करना मुश्किल हो सकता है। परीक्षा सूचनाओं से अपडेट रहना नवीनतम जेईई मेन परीक्षा अपडेट से अवगत रहना महत्वपूर्ण है। आवेदन पत्र, परीक्षा तिथियों, पाठ्यक्रम और पैटर्न में बदलाव की जानकारी के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) की वेबसाइट को बार-बार देखें। घर पर जेईई मेन की तैयारी के लिए एक अनुशासित रणनीति, इंटरनेट संसाधनों का कुशल उपयोग और नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। आप इसकी संरचना के बारे में जागरूक होकर, एक समझदार अध्ययन कार्यक्रम की योजना बनाकर और अपनी प्रेरणा बनाए रखकर परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपनी संभावनाओं को बेहतर बना सकते हैं। यह कभी न भूलें कि इस सड़क पर आपके सबसे मूल्यवान संसाधन दृढ़ता और आत्म-विश्वास हैं। यदि आपके पास सही दृष्टिकोण और मानसिकता है तो घर बैठे आराम से जेईई मेन में सफल होना संभव है।

एक गौसेवक से मुलाकात

देश की सडक़ों की दयनीय दशा के मद्देनजऱ भारत की लोक कल्याणकारी सरकार ने दस साल पहले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोबाइल स्पीड ब्रेकर सेवा योजना आरम्भ की थी। पर अन्य योजनाओं की तरह इस सेवा को विभिन्न कारणों से देश भर में लागू नहीं किया जा सका। लेकिन इसके बावजूद यह सेवा देश के पूर्वोत्तर इलाकों और गोवा-केरल आदि राज्यों को छोडक़र अन्य राज्यों में व्यापक स्तर पर सफलता से काम कर रही है। देश की संवेदनशील सरकार जिन योजनाओं को चुनावी सफलता के हिसाब से लागू करती है, उनमें प्रधानमंत्री मोबाइल स्पीड ब्रेकर सेवा योजना सर्वोपरि है। भले इस सेवा को सरकार अखिल भारतीय स्तर पर लागू नहीं करवा सकी हो, बावजूद इसके हमारे चरित्र की तरह सडक़ों की हालत पूरे देश में एक जैसी है। भले किसी राज्य में लोग गौमांस खाते हों या न खाते हों, पर हमारा राष्ट्रीय चरित्र कोहिनूर हीरे की तरह पूरे देश भर में एक समान आभा बिखेरता है। अभी दो दिन पहले की बात है। मैं स्कूटर पर बाज़ार जा रहा था कि चौबीस गुणा सात उपलब्ध अखिल भारतीय प्रधानमंत्री मोबाइल स्पीड ब्रेकर सेवा के तहत भटकने वाले एक गौपिता ने मुझे सींग मार कर गिरा दिया। गनीमत यह रही कि सेवा शुल्क चुकाए जाने पर उपलब्ध चालक फ्रेंडली पुलिस सेवा के बावजूद मैंने हैलमेट डाला हुआ था। लेकिन शरीर के बाकी अंगों के लिए अभी कोई हैलमेट नहीं बना है। इसलिए कई जगह छिलने और खरोंचों के साथ घर वापस पहुंचा। डॉक्टर कहता चाहे न कहता, हालत देखकर साफ था कि कम से कम हफ्ता भर शरीर को आराम देना ही पड़ेगा। मेरे पड़ोसी गौसेवक झुन्नू लाल को जैसे ही पता चला कि मैं स्कूटर से गिर गया हूं, दौड़े-दौड़े मिलने चले आए। गौसेवकों का कुछ और लाभ होता हो या नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि वे आपदा में अवसर या अवसर में आपदा ढूंढ़ ही लेते हैं।

गौधन भले न रंभाए हो, लेकिन गौसेवकों से रंभाने के मामले में कोई नहीं जीत सकता। यहां तक कि सदन में माननीयों का शोर भी उनके रंभाने के सामने फीका पड़ जाता है। समूचे विश्व में आज गौसेवकों के रंभाने की पुरज़ोर गूंज सुनी जा सकती है। वे अपने काम के प्रति इतने चौकस और संवेदनशील हैं कि अब उन्होंने हिंदू-मुसलमान के बीच भेद करना भी छोड़ दिया है। सडक़ों पर आवारा फिरने वाले गौधन की रक्षा के लिए अब वे किसी की भी जान ले सकते हैं। उनको देखते ही मुझे उन्हें छेडऩे की सूझी। मैं बोला, 'देखो! गौपिता कितने भले थे कि उन्होंने केवल सिर ही हिलाया था। सींग मारा पर घुसाया नहीं। अगर कहीं दौड़ा दिया होता तो इतनी भीड़ में वह मुझे प्यार किए बिना न मानते। लेकिन उनके सिर हिलाने भर से मुझे खाट पर कम से कम एक हफ्ता रहना ही पड़ेगा। अगर दौड़ाया होता तो मुझसे मिलने के लिए आपको यमराज के दरबार में आना पड़ता।' झुन्नू लाल किसी ख़ानदानी हकीम की तरह ख़ानदानी गौसेवक थे। उनके पिता जी राष्ट्रीय गौसेवक संघ के कट्टर कार्यकर्ता थे। उन्होंने कई गौरक्षक आन्दोलनों में भाग लिया था और कइयों की अगुवाई की थी। एक बार उन्होंने गौरक्षा के लिए संसद का घेराव भी किया था। किसी मंझे हुए नेता की तरह गौसेवक झुन्नू लाल बोले, 'यार! भगवान का शुक्र है कि गौपिता ने तुम्हें दौड़ाया नहीं। आखिर है तो जानवर ही। लेकिन फिर भी उनमें अच्छे-बुरे की तमीज़ होती है। अगर कोई विधर्मी होता या तुम्हारे दिल में हिंसा होती तो वह तुम्हें ज़रूर दौड़ाता।' मैं उन्हें बधाई देते हुए बोला, 'सुना है आपके विश्व गुरु को बछड़ा हुआ है। उन्होंने उसका भला सा नाम भी रखा है, दीपज्योति। पोर्ट ब्लेयर का नाम भी बदल कर उन्होंने श्री विजय पुरम रखा है। पर जिस तरह विश्व गुरु सोशल मीडिया पर बछड़े से प्यार करते दिखे, अगर उतना प्यार उन्होंने अपनी बीवी से किया होता तो आज उनका नूर चश्म भी देश की किसी संवैधानिक या धनी खेल संस्था का कर्ता-धर्ता होता।'

आसान नहीं होगा जीएम पर नीति बनाना

डा. अंजनी कुमार झा

यह बहुत खेद की बात है कि जीएम सरसों के शाकनाशी सहनशील होने के तथ्य को शुरू में छुपाया गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि डीएमएच 11 का परीक्षण करते समय, इसकी शाकनाशी सहिष्णुता के बारे में कोई परीक्षण नहीं किया गया था

हाल ही में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) सरसों की व्यावसायिक खेती के संबंध में एक विभाजित निर्णय दिया। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने अनुमोदन प्रक्रिया में खामियों और पर्यावरण तथा स्वास्थ्य प्रभावों पर पर्याप्त विचार की कमी का हवाला देते हुए जीएम सरसों की व्यावसायिक बिक्री और पर्यावरण रिलीज के खिलाफ फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति करोल ने फील्ड ट्रायल जारी रखने का समर्थन किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि उन्हें सख्त सुरक्षा उपायों के साथ आगे बढना चाहिए। जीएम फसलों की व्यावसायिक खेती के संबंध में यह मामला (सुमन सहाय और अरुणा रोड्रिग्स और अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य) वर्ष 2004 से भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, लेकिन जीएम फसलों के पैरोकार जीएमओ की व्यावसायिक रिलीज के लिए अदालत की मंजूरी अभी तक नहीं ले पाए। इस मामले से एक नहीं, बल्कि कई विवादास्पद मुद्दे जुड़े हैं, जिन पर अदालत इतने लंबे समय से निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। 23 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया विभाजित निर्णय एक बार फिर इस मामले की जटिलताओं को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह इस नीति को तैयार करने के लिए 4 महीने के भीतर सभी हितधारकों और विशेषज्ञों से परामर्श करे।

साथ ही पीठ ने मामले को उचित पीठ द्वारा आगे के निर्णय के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया है। हालांकि न्यायालय ने सरकार को विभिन्न हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ परामर्श के बाद 4 महीने के भीतर जीएम पर एक नीति तैयार करने का निर्देश दिया है। किसी भी तरह से, एक ऐसा मुद्दा जिसने देश और दुनिया में पिछले 25 साल से भी अधिक समय से भारी बहस और गर्माहट पैदा की है, जहां विशेषज्ञ विभाजित हैं, लोग न केवल चिंतित हैं, बल्कि जीएम के दुष्प्रभावों के कारण डरे हुए हैं, जहां एक मजबूत नियामक तंत्र का पूर्ण अभाव है, जहां सर्वोच्च न्यायालय स्वयं नियामक तंत्र की कमी के कारण इस जीएम के पक्ष में निर्णय देने के लिए तैयार नहीं है, जीएमओ के मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए सुरक्षित होने के भी सबूत नहीं हैं, जहां कई देशों ने मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की चिंताओं के कारण पहले ही जीएम फसलों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, यह बहुत कम संभावना है कि सरकार हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ परामर्श के बाद 4 महीने में जीएम पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का कार्य पूरा कर पाएगी। यह पहली बार नहीं है कि जीएम फसलों के लिए परामर्श तंत्र अपनाया जा रहा है। इससे पहले, यूपीए सरकार के दौरान बीटी बैंगन के वाणिज्यिक विमोचन के संबंध में तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्री जयराम रमेश के साथ सार्वजनिक सुनवाई हुई थी। यह ध्यान देने योग्य है कि इन सार्वजनिक सुनवाई के अंत में, मंत्री जयराम रमेश ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए बीटी बैंगन के वाणिज्यिक रिलीज पर रोक लगा दी थी।

क्या हो परामर्श की उचित संरचना : जबकि, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को हितधारकों और विशेषज्ञों के परामर्श आयोजित करने का निर्देश दिया है, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इन परामर्शों की संरचना क्या हो सकती है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर ये परामर्श हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा कई विवादास्पद मुद्दों को लंबे समय से सूचीबद्ध किया गया है, जो परामर्श प्रक्रिया का आधार बन सकते हैं, और निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहला मुद्दा, जिस पर विशेषज्ञों के बीच आम सहमति का अभाव है, वह जीएम फसलों की उच्च उत्पादकता का दावा है। दिलचस्प बात यह है कि सरकार और जीएम समर्थकों का तर्क यह है कि देश बड़ी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात कर रहा है, जिनमें से अधिकांश जीएम तेल हैं। सरकार का दावा है कि डीएमएच 11 को अपनाने से आयात पर निर्भरता कम करने और डीएमएच 11 की अधिक उत्पादकता के कारण किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है। लेकिन जबकि डीएमएच 11 के डेवलपर (अनुसंधानकर्ता) के अनुसार भी इसकी उत्पादकता 2200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक नहीं है, देश में सरसों की कई अन्य संकर किस्मों की अपेक्षित उपज 2500 किलोग्राम से 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक है। भारतीय सरसों और रेपसीड संस्थान के पूर्व निदेशक डा. धीरज सिंह के एक शोध पत्र के अनुसार, राजस्थान में किसानों द्वारा उगाई गई किस्मों आरएस 1706, आरएच 1424 और आरएच 725 की उत्पादकता (जैसा कि सरकार ने खुद घोषित किया है), क्रमशः 2613 किलोग्राम, 2604 किलोग्राम, 2642 किलोग्राम है। विवाद का दूसरा मुद्दा बौद्धिक संपदा अधिकारों का है।

किसान संगठनों को चिंता है कि एक बार जीएमओ अपनाने के बाद, बीज पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एकाधिकार हो जाएगा और किसानों पर बीजों पर रॉयल्टी के रूप में बोझ बढ़ जाएगा। उनकी आशंकाएं बेवजह नहीं हैं। हम देखते हैं कि किसानों को असफल बीटी कपास के बीज के लिए भी बहुत अधिक कीमत (लगभग 8000 करोड़ रुपए) चुकानी पड़ी, क्योंकि बीटी कपास के बीज की कीमत का एक बड़ा हिस्सा विशेषता शुल्क था। वर्तमान डीएमएच 11 बीज को हालांकि स्वदेशी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। उसमें भी बायर कंपनी की प्रौद्योगिकी के कुछ गुणों का उपयोग किया गया है, जिसके कारण बौद्धिक संपदा का विषय किसान हितों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर उनका प्रभाव है। जबकि जीएम के समर्थक बिना किसी वैध तर्क के दावा करते हैं कि इससे आयातित खाद्य तेलों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी (यदि डीएमएच 11 को अनुमति दी जाती है), तथ्य यह है कि खाद्य फसलों में जीएम अपनाने के बाद हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी अपना लाभ खो सकते हैं। आज हम हमारे गैर-जीएम टैग के कारण, लगभग 54 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के खाद्य उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं।

एक बार जब खाद्य पदार्थों में जीएम की अनुमति दे दी जाती है, तो हम इस महत्वपूर्ण लाभ को खो देंगे, क्योंकि आयात करने वाले देश, जहां जीएम की अनुमति नहीं है, भारतीय खाद्य आयातों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। चौथा विवादास्पद मुद्दा जीएम बीजों के भारतीय खाद्य और आयुर्वेद पर प्रभाव के बारे में है। जीएम फसलें खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को बदल देती हैं, जो हमारे भोजन का आवश्यक हिस्सा हैं। उदाहरण के लिएए सरसों का साग। इसी तरह, भारतीय सरसों के आयुर्वेद में कई औषधीय उपयोग हैं, जिन्हें हम खो सकते हैं। जीएमओ पर बहस में पांचवां मुद्दा शाकनाशी सहिष्णुता है। यह उल्लेखनीय है कि लगभग 88 प्रतिशत जीएम फसलों को शाकनाशी (हरबिसाइड) सहनशील बनाया गया है। इसका मतलब है, जीएम फसलें आम तौर पर शाकनाशियों के उपयोग को बढ़ाती हैं, जिससे विषाक्तता बढ़ जाती है। लगभग सभी प्रमुख शाकनाशी कैंसरकारी साबित हुए हैं। यह बहुत खेद की बात है कि जीएम सरसों के शाकनाशी सहनशील होने के तथ्य को शुरू में छुपाया गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि डीएमएच 11 का परीक्षण करते समय, इसकी शाकनाशी सहिष्णुता के बारे में कोई परीक्षण नहीं किया गया था। जब जागरूक नागरिकों और विशेषज्ञों ने जीईएसी के इस कृत्य को उजागर किया तो समिति ने हास्यास्पद शर्त लगा दी कि किसी भी स्थिति में किसान खरपतवारनाशकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। विवादास्पद मुद्दों की सूची में कई अन्य बिंदु शामिल हैं, जिन पर विचार किए बिना हम इस विषय पर एक समझपूर्ण नीति बनाने के अपने कत्र्तव्य में विफल हो सकते हैं। इन मुद्दों में बीज संप्रभुता पर प्रभाव व जैव विविधता पर प्रभाव भी शामिल हैं।

अनिल अंबानी की बदलने वाली है तकदीर? रिलायंस इन्फ्रा के शेयरों में तगड़ा उछाल

परिवहन विशेष न्यूज

रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर अनिल अंबानी के अगुआई वाले रिलायंस ग्रुप का हिस्सा है। कंपनी बिजली सड़क मेट्रो रेल और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन सेवाएं देती है। कंपनी रक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में कई परियोजनाओं के कार्यान्वयन संचालन और रखरखाव में भी लगी हुई है। इसके शेयरों में मंगलवार को काफी अच्छी तेजी दिखी।

नई दिल्ली। अनिल अंबानी (Anil Ambani) की रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर (Reliance Infrastructure) के शेयरों में मंगलवार को जबरदस्त तेजी आई। इसने दिन में कारोबार के दौरान 238 रुपये का हाई बनाया और आखिर में 8.97 फीसदी उछाल के साथ 235.44 रुपये पर बंद हुआ। रिलायंस इन्फ्रा के शेयरों में तेजी कंपनी के उस एलान के बाद आई, जिसमें उसने दीर्घावधि फंड जुटाने के लिए बोर्ड मीटिंग की जानकारी दी।

यह मीटिंग गुरुवार (19 सितंबर) को होगी। हालांकि, कंपनी ने अभी यह नहीं बताया है कि वह कितना फंड जुटाएगी और किस तरीके जुटाएगी।

रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर का वित्तीय प्रदर्शन

रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्तीय मोर्चे पर अब काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। उसने 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही में अपने घाटे को सालाना आधार पर 65.2 फीसदी कम करके 233.74 करोड़ रुपये कर दिया। एक साल पहले घाटा 672.86 करोड़ रुपये था। इस तिमाही में कंपनी की कुल आय 7,256.21 करोड़ रुपये रही, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 5,645.32 करोड़ रुपये थी। 31 मार्च तक कंपनी के इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्टिंग (E&C) डिवीजन के पास कुल 1,974.64 करोड़ रुपये की ऑर्डर बुक थी।

क्या करती है रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर

रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर अनिल अंबानी के अगुआई वाले रिलायंस ग्रुप का हिस्सा है। कंपनी बिजली, सड़क, मेट्रो रेल और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन सेवाएं देती है। कंपनी रक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में कई परियोजनाओं के कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव में भी लगी हुई है। इसने मुंबई मेट्रो लाइन वन प्रोजेक्ट को भी किया है। इसकी मौजूदगी ऊर्जा व्यवसायों तक भी फैली हुई है।

रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के शेयरों का हाल

रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के शेयरों पिछले काफी समय से उतार-चढ़ाव दिख रहा है। कंपनी ने पिछले एक साल में 8 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया। हालांकि, पिछले एक साल में निवेशकों को कंपनी से करीब 33 फीसदी का रिटर्न मिला है। रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर का मार्केट कैप 93 अरब रुपये का है। इसका 52 हफ्ते का हाई लेवल 308 रुपये है, जबकि नीचे की तरफ यह 144 रुपये तक आया है।

20 हजार को बनाया एक करोड़; रिटर्न देने के तोड़े सारे रिकॉर्ड; लगातार लग रहा अपर सर्किट

परिवहन विशेष न्यूज

श्री अधिकारी ब्रदर्स (sri adhikari brothers share)। इसमें लगातार अपर सर्किट ही लग रहा है। इसके चलते एक्सचेंजों ने श्री अधिकारी ब्रदर्स के शेयर की सर्किट लिमिट घटाकर 2 फीसदी कर दी। इसका मतलब है कि यह स्टॉक अब एक दिन में 2 फीसदी से ज्यादा घट या बढ़ नहीं सकता। फिर भी श्री अधिकारी ब्रदर्स के शेयरों की रफ्तार नहीं थम रही।

नई दिल्ली। शेयर मार्केट में इन बजाज हाउसिंग फाइनेंस की धूम है। इसने पहले आईपीओ निवेशकों का पैसा लिस्टिंग पर डबल किया और फिर लगातार दो दिन 10-10 फीसदी का अपर सर्किट लगा। लेकिन, बजाज हाउसिंग ने निवेश को सिर्फ ढाई गुना किया। लेकिन, एक ऐसा शेयर है, जिसने पिछले एक साल में रिटर्न के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक साल पहले आपने इस शेयर सिर्फ 20 हजार रुपये भी लगाए होते, तो आज आप करोड़पति होते।

यह शेयर है श्री अधिकारी ब्रदर्स (sri adhikari brothers share)। इसमें लगातार अपर सर्किट ही लग रहा है। इसके चलते एक्सचेंजों ने श्री अधिकारी ब्रदर्स के शेयर की सर्किट लिमिट घटाकर 2 फीसदी कर दी। इसका मतलब है कि यह स्टॉक अब एक दिन में 2 फीसदी से ज्यादा घट या बढ़ नहीं सकता। इसका शेयर मंगलवार को 2 फीसदी उछल कर 718.80 रुपये पर पहुंच गया। पिछले एक महीने में यह शेयर करीब 52 फीसदी का रिटर्न दे चुका है।

श्री अधिकारी ब्रदर्स ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

श्री अधिकारी ब्रदर्स ने रिटर्न देने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह शेयर दिसंबर 2023 में 1 रुपये के आसपास था। यहां तक जनवरी 2024 में भी इसकी कीमत 4 रुपये के करीब थी। वहां से इसने जो रफ्तार पकड़ी, वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही। अगर आपने इस साल की शुरुआत में भी श्री अधिकारी ब्रदर्स के शेयर में 1 लाख रुपये लगाए होते, तो आज उसकी वैल्यू करीब 24,686.21 फीसदी बढ़कर लगभग 2.5 करोड़ रुपये हो गई होती।

पिछले एक साल के रिटर्न की बात करें, तो श्री अधिकारी ब्रदर्स ने करीब 55,192.31 फीसदी का हैरतंगेज रिटर्न दिया है। इसका मतलब है कि अगर आपने एक साल पहले 1 लाख रुपये के शेयर खरीदे होते, तो आज उसकी वैल्यू करीब 5.5 करोड़ रुपये होती। वहीं, अगर आपने एक साल पहले सिर्फ 20,000 हजार रुपये का भी निवेश किया होता, तो आज उसकी वैल्यू करीब 1.1 करोड़ रुपये होती और आप करोड़पति बन गए होते।

क्या करती है श्री अधिकारी ब्रदर्स

श्री अधिकारी ब्रदर्स टेलीविजन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड मुंबई स्थित एक टेलीविजन नेटवर्क कंपनी है। श्री अधिकारी ब्रदर्स ने 1990 के दशक में दूरदर्शन, स्टार प्लस और अन्य टेलीविजन चैनलों के लिए टीवी सीरियल बनाए। उन्होमने 1999 में अपना कॉमेडी चैनल शुरू किया, सब टीवी। इस पर कॉमेडी सर्कस जैसे शो आते थे, जिन्होंने हास्य जगत को कपिल शर्मा और सुदेश लहरी जैसे बड़े नाम दिए।

हालांकि, श्री अधिकारी ब्रदर्स ने 6 साल बाद सब टीवी को सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया को बेच दिया गया। उन्होंने 2013 में एक हिंदी एंटरटेनमेंट चैनल लॉन्च किया, दबंग। हालांकि इसे 2016 में पूरी तरह से भोजपुरी मूवी चैनल बना दिया गया। उन्होंने 2022 में एक मराठी मनोरंजन चैनल के रूप में माईबोली लॉन्च किया, लेकिन बाद में इसे एक म्यूजिक चैनल में बदल दिया।

यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भूले, तो हो जाएगी परेशानी; जान लें रिकवर करने का आसान तरीका

परिवहन विशेष न्यूज

How to recover UAN यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) का इस्तेमाल कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड खाते को पहचानने के लिए किया जाता है। यह एक 12-अंकों का नंबर होता है जो कर्मचारी के पूरे कार्यकाल में एक ही रहता है भले ही वह कितनी भी बार नौकरी बदल ले। इसकी मदद से आप अपने पीएफ अकाउंट में जमा और निकासी कर सकते हैं। आइए जानते हैं UAN रिकवर करने का तरीका।

नई दिल्ली। एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) मेंबर्स के लिए UAN यानी Universal Account Number काफी अहम होता है। यह पासबुक मर्ज करने से लेकर बैलेंस चेक जैसे कामों को काफी आसान कर देता है। वहीं, इसके न होने की स्थिति में कई दिक्कतें भी होती हैं। इसके बगैर आप अपने EPFO अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ऐसे में हम आपको UAN पता लगाने का बहुत आसान तरीका बताने वाले हैं, ताकि आप जरूरत के वक्त अपना UAN जान सकें।

UAN क्या होता है?

यूनिवर्सल अकाउंट नंबर का इस्तेमाल असल में कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड (पीएफ) खाते को पहचानने के लिए किया जाता है। यह एक 12-अंकों का नंबर होता है, जो कर्मचारी को उसके पूरे कार्यकाल में एक ही रहता है। भले ही वह कितनी भी बार नौकरी बदल ले। इसके जरिए कर्मचारी अपने पीएफ अकाउंट से जमा और निकासी भी कर सकते हैं। इसकी मदद से पीएफ अकाउंट को मर्ज या फिर समाप्त भी किया जा सकता है।

UAN कैसे मिलता है?

अगर आप ऐसी कंपनी में काम करते हैं, जो EPFO के दायरे में आती है, तो नौकरी ज्वाइन करने के बाद वह आपका पीएफ अकाउंट खुलवाएगी और आपको UAN नंबर दे देगी। यह पहली बार नौकरी ज्वाइन करने वालों के लिए ही है। अगर आप नौकरी बदलते हैं, तो नई कंपनी में आपका सिर्फ नया पीएफ अकाउंट खुलेगा। UAN नंबर वही पहले वाला रहेगा। हालांकि, आप इसे मर्ज कर सकते हैं, UAN की मदद से।

UAN भूल गए तो?

UAN 12 अंकों का होता है। अगर आपने इसे कहीं सहेजकर नहीं रखा, तो भूलने की संभावना काफी अधिक रहती है। हालांकि, UAN को रिकवर करने का तरीका भी काफी आसान है।

- UAN की वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं।
- राइट हैंड साइड पर दिख रहे Important Links में जाकर Know your UAN पर क्लिक करें।
- अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालकर Request OTP पर क्लिक करें।
- आपके रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी और कैप्चा कोड डालकर Validate OTP पर क्लिक करें।
- अब पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार या पैन और कैप्चा कोड डालकर Show My UAN पर क्लिक करें।
- Show My UAN पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आ जाएगा।

थोक महंगाई में लगातार दूसरे महीने गिरावट, पर सब्जियों का भाव बढ़ा रहा चिंता

पिछले सप्ताह जारी आंकड़ों से पता चला है कि सब्जियों की ऊंची कीमतों के कारण अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति 3.65 प्रतिशत थी। यह जुलाई के 3.60 प्रतिशत से अधिक थी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) मौद्रिक नीति तैयार करते समय मुख्य रूप से खुदरा मुद्रास्फीति को ध्यान में रखता है। उसने अगस्त में लगातार नौवीं बार बेंचमार्क ब्याज दर या रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा।

नई दिल्ली। सब्जियों, खाद्य पदार्थों और ईंधन के सस्ता होने से थोक मुद्रास्फीति अगस्त में चार महीने के निचले स्तर 1.31 प्रतिशत पर आ गई। हालांकि, प्याज और आलू की कीमतों में तेजी रही। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति में लगातार दूसरे महीने गिरावट आई है, जबकि मई में यह 3.43 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। जुलाई में 2.04 प्रतिशत और अगस्त, 2023 में इसमें 0.46 प्रतिशत की गिरावट आई थी।

खुदरा मुद्रास्फीति की बात करें तो सब्जियों की बढ़ती कीमतों के कारण यह अगस्त में 3.65 प्रतिशत रही। यह जुलाई के 3.60 प्रतिशत से अधिक है। आरबीआइ मौद्रिक नीति तैयार करते समय मुख्य रूप से खुदरा मुद्रास्फीति को ध्यान में रखता है। आरबीआइ ने अगस्त की मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर को लगातार नौवीं बार 6.5 प्रतिशत पर यथावत रखा था।

उद्योग मंत्रालय के मुताबिक, 'अगस्त 2024 में खाद्य पदार्थों, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों, अन्य विनिर्माण, कपड़ा विनिर्माण तथा मशीनरी और उपकरण आदि के विनिर्माण की कीमतों में वृद्धि हुई।' आंकड़ों के अनुसार, खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति अगस्त में 3.11 प्रतिशत रही, जबकि जुलाई में यह 3.45 प्रतिशत थी। सब्जियों की कीमतों में अगस्त में 10.01 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। आलू और प्याज की मुद्रास्फीति अगस्त में क्रमशः 77.96 प्रतिशत और 65.75 प्रतिशत के उच्च स्तर पर बनी रही।

वित्तीय सेवा कंपनी बार्कलेज के मुताबिक, 'अगस्त में थोक मूल्य सूचकांक में नरमी का कारण खाद्य (सब्जी) कीमतों में क्रमिक गिरावट है। बार्कलेज ने यह भी कहा है कि ऊर्जा और धातु की कीमतों में गिरावट के कारण विनिर्माण लागत में कमी आने से मुख्य उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति पर प्रभाव पड़ने का जोखिम कम हो गया है। अगस्त माह में विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति 1.22 प्रतिशत रही। ईंधन और बिजली श्रेणी में मुद्रास्फीति जुलाई में 1.72 प्रतिशत के मुकाबले अगस्त में 0.67 प्रतिशत रही।

ओला इलेक्ट्रिक फिर लगाएगा टॉप गियर, ब्रोकरेज बोले- 50 फीसदी तक बढ़ सकता है भाव

Ola Electric Mobility Share Price ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों ने फ्लैट लिस्टिंग के बाद निवेशकों को करीब 100 फीसदी का रिटर्न दिया। हालांकि फिर ओला के शेयरों में गिरावट आई। यह 157 रुपये के रिकॉर्ड हाई स्तर से करीब 30 फीसदी नीचे आ गया। अब विदेशी ब्रोकरेज फर्मों के नए प्राइस टारगेट्स से ओला के शेयरों में फिर से हलचल बढ़ सकती है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Ola Electric Mobility Share Price) के शेयरों में जबरदस्त तेजी आने का अनुमान है। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर आईपीओ के बाद फ्लैट लिस्ट हुए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने 100 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया। हालांकि, उसके बाद ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में काफी करेक्शन भी हुआ।

अब भाविश अग्रवाल के मालिकाना हक वाली ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में फिर से तेजी आ रही है। इसमें मंगलवार को शुरुआती कारोबार में 5 फीसदी से अधिक की तेजी आई। दरअसल, दो विदेशी ब्रोकरेज फर्मों ने ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को 'Buy' रेटिंग के साथ कवर करना शुरू किया है। मंगलवार दोपहर 12 बजे तक ओला इलेक्ट्रिक के शेयर 5.81 फीसदी के उछाल के साथ 113.85 रुपये पर कारोबार कर रहे थे।

बोफा सिक्योरिटीज ने दी 'Buy' रेटिंग

बोफा सिक्योरिटीज (BofA Securities) का मानना है कि ओला इलेक्ट्रिक से निवेशकों को शानदार रिटर्न मिल सकता है। BofA सिक्योरिटीज ने ओला इलेक्ट्रिक पर 145 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। इसके मुताबिक, ओला इलेक्ट्रिक में सोमवार के बंद भाव से करीब 35 फीसदी आ सकती है।

BofA सिक्योरिटीज के मुताबिक, भारत के टू-व्हीलर सेगमेंट में अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों व्हीकल का योगदान अभी 6.5 फीसदी है। इलेक्ट्रिक स्कूटरों का दाम अब पेट्रोल स्कूटरों से भी कम हो गई है। यह EV मार्केट के लिए अहम मोड़ साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी पकड़ मजबूत की है। उसने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, फंडिंग एक्सेस और ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मोर्चे को काफी कुशलता से संभाला है।

गोल्डमैन सैक्स ने दिया 160 का टारगेट प्राइस

वहीं, प्रतिष्ठित ग्लोबल ब्रोकरेज गोल्डमैन सैक्स (Goldman Sachs) ने भी ओला इलेक्ट्रिक को खरीदने की सलाह दी है। उसने टारगेट प्राइस 160 रुपये दिया है। इसके हिसाब से इनवेस्टर्स को 50 फीसदी तक का तगड़ा रिटर्न मिल सकता है। गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से ओला इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट में लंबी अवधि में अच्छी बढ़त मिल सकती है।

ब्रोकरेज का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2024 से 2030 के बीच कंपनी का रेवेन्यू 40 फीसदी CAGR की दर से बढ़ सकती है। इससे कंपनी 2030 तक सब्सिडी के बिना भी फ्री कैश फ्लो के स्तर पर ब्रेक-ईवन तक पहुंच सकती है। इसका सकारात्मक असर उसके शेयरों पर भी देखने को मिलेगा। हालांकि, Ola Electric के सामने कॉम्पिटीशन, इन-हाउस सेल मैन्युफैक्चरिंग के फ्यूचर और डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर नेटवर्क जैसी कई संभावित चुनौतियां भी हैं।

आसमान पर पहुंचने वाली है गहनों की डिमांड, क्या कीमतों पर भी दिखेगा असर?

परिवहन विशेष न्यूज

भारत में सोने की गहनों की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है। सीमा शुल्क में भारी कटौती और त्योहारी मांग के चलते अगस्त में सोने का आयात दोगुना से अधिक 10.06 अरब डॉलर के रिकार्ड उच्चस्तर पर पहुंच गया है। फेस्टिव और शादियों के सीजन के दौरान गहनों की डिमांड में और तेजी आने की उम्मीद है। इसका असर सोने की कीमतों पर भी दिख सकता है।

नई दिल्ली। देश के आभूषण बाजार में खरीदारी रुझान में बदलाव देखने को मिल रहा है। ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने ताजा रिपोर्ट में कहा है कि कैलेंडर वर्ष 2024 की दूसरी छमाही में स्वर्ण आभूषणों की मांग में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। इसमें आगामी त्योहारी सीजन का प्रमुख योगदान रहेगा। रिपोर्ट के अनुसार, पहली तिमाही में अमीरों ने स्वर्ण आभूषणों की खरीदारी की। वहीं, दूसरी तिमाही में कम कीमत वाले आभूषणों की बिक्री में वृद्धि देखी गई।

आभूषणों की बिक्री में अर्ध-शहरी और ग्रामीण बाजार भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि खुदरा विक्रेता ग्राहकों की मांग में अपेक्षित वृद्धि को पूरा करने के लिए अपने स्टोर नेटवर्क का विस्तार कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि आभूषणों की बिक्री में सुधार का प्रमुख संकेतक सोने का आयात है और अगस्त में इसके आयात में मजबूत सुधार दिखा है।

सोने का आयात दोगुना से अधिक हुआ

सीमा शुल्क में भारी कटौती और त्योहारी मांग के चलते अगस्त में सोने का आयात दोगुना से अधिक 10.06 अरब डॉलर के रिकार्ड उच्चस्तर पर पहुंच गया। पिछले साल की समान अवधि में सोने का आयात 4.93 अरब डॉलर रहा था। सोने के आयात का देश के चालू खाता घाटे पर असर पड़ता है। अप्रैल से जुलाई के दौरान सोने का आयात 4.23 प्रतिशत घटकर 12.64 अरब डॉलर हो गया। पिछले वित्त वर्ष में सोने का आयात 30 प्रतिशत बढ़कर 45.54 अरब डॉलर रहा था।

स्विटजरलैंड से सबसे ज्यादा आयात

स्विटजरलैंड से सोने का सबसे ज्यादा आयात होता है और उसकी हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत है। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात से 16 प्रतिशत और दक्षिण अफ्रीका की आयात में हिस्सेदारी लगभग 10 प्रतिशत है। देश के कुल आयात में सोने की हिस्सेदारी पांच प्रतिशत से अधिक है। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता है। आयात मुख्य रूप से आभूषण उद्योग की मांग को पूरा करता है। बजट में सरकार ने आयात शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर छह प्रतिशत कर दिया था।

क्या बीजेपी में शामिल होंगे मनोज मुंतशिर? BJP नेताओं से की मुलाकात, कहा- यह DNA हमें सूट करता है

मनोज मुंतशिर के भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं चल रही हैं। पिछले कुछ दिनों में ही महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित तीन भाजपा नेताओं से उनकी मुलाकात हो चुकी है। जब मनोज मुंतशिर से उनके भाजपा में शामिल होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसका उत्तर हां या ना में देने के बजाय सिर्फ इतना कहा कि भाजपा का डीएनए हमें सूट करता है।

मुंबई: गीतकार एवं पटकथा लेखक मनोज मुंतशिर के भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं चल रही हैं। पिछले कुछ दिनों में ही महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित तीन भाजपा नेताओं से उनकी मुलाकात हो चुकी है। मनोज मुंतशिर का पूरा नाम मनोज शुक्ला है। वह मूलतः उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले की गौरीगंज तहसील के रहनेवाले हैं। पिछले कुछ दिनों में ही मनोज मुंतशिर ने मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार, राज्य सरकार में वरिष्ठ मंत्री सुधीर मुनगंटीवार एवं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। मंगलवार दोपहर बाद उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद जब मनोज मुंतशिर से उनके भाजपा में शामिल होने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इसका उत्तर हां या ना में देने के बजाय सिर्फ इतना कहा कि भाजपा का डीएनए हमें सूट करता है। मनोज मुंतशिर मुंबई में वह वर्सोवा क्षेत्र में रहते हैं।

क्यों बढ़ रहा बीजेपी से मेलजोल?

यह उत्तर भारतीयों की बहुलता वाला क्षेत्र माना जाता है। इसलिए भाजपा आगामी विधानसभा क्षेत्र में उन्हें इस क्षेत्र से प्रत्याशी बनाकर अपना उत्तर भारतीय कोटा भी पूरा कर सकती है। बता दें कि मुंबई में उत्तर भारतीय मतदाताओं की संख्या कई विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक है। यह वर्ग कभी कांग्रेस का प्रतिबद्ध मतदाता माना जाता था। किंतु 2014 में राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के उभार के बाद से यह पूरी तरह कटकर भाजपा के साथ आ गया था।

मुंबई में कोई ऐसा सुपरिचित उत्तरभारतीय चेहरा नहीं

लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर इस वोटबैंक में बंटवारा हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) का जो गणित अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लिए बैठाने में सफल रहे, उसका उसर मुंबई में भी देखा गया है।

"सामाजिक व्यवस्था में पीछे छोड़ दिये गए अपने बन्धुओं को साथ लेकर चलना चाहती हैं आरएसएस"

राष्ट्रवादी चिंतक राजेश खुराना

अपील - जाति जनगणना का इस्तेमाल छुआछूत के कारण पिछड़ रहे समुदाय और जातियों के कल्याण के लिए होना चाहिए: राष्ट्रवादी चिंतक राजेश खुराना

आगरा,संजय साग़र सिंह। लोकसभा चुनाव में इस साल बीजेपी को झटका लगा। इसकी बड़ी वजह रही कि विपक्ष एससी/एसटी वोटरों में ये भ्रम फैलाने में सफल रहा कि आरक्षण और संविधान ख़तरे में है, और इस आग में घी डालने का काम कुछ बीजीपी में अपना दबदबा क़ायम रखने बाले नेताओं ने भी खुले मंच से किया। अगड़े वोटर नाराज ना हो जाएं इसलिए अलाकमान भी चुप रहा और चुनावों में अपनी चुप्पी का नुकसान भी झेल रहे हैं, लेकिन इस बीच आरएसएस का दलितों और पिछड़ों के बीच और ज्यादा फोकस रहा, क्योंकि उनको पता हैं कि हिंदू वोट बैंक दलितों पिछड़ों की भागीदारी के बिना अधूरा है। इसीलिए जाति जनगणना का समर्थन करके संघ सामाजिक व्यवस्था में पीछे छोड़ दिये गए अपने बन्धुओं को साथ लेकर चलना चाहता हैं।

इस विषय पर वरिष्ठ राष्ट्रवादी चिंतक एवं आरएसएस की विचारधारा की गहरी समझ रखने वाले वरिष्ठ समाजसेवी राजेश खुराना ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामाजिक व्यवस्था में पीछे छोड़ दिये गए अपने बन्धुओं को साथ लेकर चलना चाहती हैं। आरएसएस ने स्पष्ट रूप से देश को बता दिया हैं कि वो जातिगत जनगणना के पक्ष में है। संघ पिछले दस सालों में बहुत बदला है। देश भर में संघ के क़रीब दो हज़ार प्रचारक होंगे और इनमें से क़रीब 20 फ़ीसदी से ज़्यादा दलित हैं। अब वो दिन दूर नहीं है, जब संघ का कोई दलित या आदिवासी स्वयंसेवक सरसंघचालक होगा। संघ की विचारधारा से सामाजिक व्यवस्था में पीछे छोड़ दिये गए अपने बन्धुओं को जोड़ना है और वो जुड़ रहे हैं। राष्ट्रहित में आरएसएस के इस व्यान से सभी जातीय पृष्ठभूमि वाले वंचित युवा धीरे-धीरे आकर्षित हो रहे हैं। संघ हमेशा से ही छुआछूत विहीन और जाति विहीन समाज का समर्थक रहा है। संघ के कार्यक्रमों और कार्यों में भी कहीं जाति नजर नहीं आती है। जाति को लेकर संघ ने अपने विचार बदलें हैं, आरएसएस का लक्ष्य हिंदू समाज में छुआछूत और ऊंच-नीच के भाव को खत्म करके सभी हिन्दुओं में एकता का भाव भरना है। संघ जाति जनगणना की वकालत कर रहा है तो इसलिए कि छुआछूत के कारण जो समुदाय पीछे रह गए हैं, उन्हें आगे आने का मौका मिलना चाहिए। संघ हमेशा समाज के सभी वर्गों को लेकर चलता है। संघ वँचित वर्ग के जीवन के सभी विषयों को लेकर चिंता भी करता है और प्रमुख बैठकों में इसकी चर्चाएं भी होती है। आरएसएस भी अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए विभिन्न स्वतंत्र हिंदू संगठनों और दबाव समूहों के साथ मजबूत संबंध बनाने की कोशिश करता रहा है। इसीलिए विहिप को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और झुग्गी बस्तियों की आबादी के बीच सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है। खासकर दिवाली से पहले। सामाजिक समरसता अभियान आमतौर पर आरएसएस शाखा स्तर के कार्यकर्ताओं के द्वारा दलितों के लिए मंदिरों और कुओं तक पहुंच सुनिश्चित करने से जुड़ा होता है।

उन्होंने कहा कि इस समय देश में माहौल बन रहा है जातिगत जनगणना के लिए, ऐसे में संघ पर संविधान विरोधी और आरक्षण विरोधी होने के आरोप पहले लगते रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस विषय पर अपना रुख स्पष्ट करना शुरू कर दिया है। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख ने जातीय जनगणना को लेकर जोरदार बयान दिया कि जातिगत आंकड़ों का इस्तेमाल अलग-अलग जातियों और समुदायों की भलाई के लिए करना चाहिए। देश

और समाज के विकास के लिए सरकार को डेटा की जरूरत पड़ती है। समाज की कुछ जाति के लोगों के प्रति विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। इन उद्देश्यों के लिए जाति जनगणना करवाना चाहिए। इसका इस्तेमाल लोक कल्याण के लिए होना चाहिए। आरएसएस ने यह भी कहा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उप-वर्गीकरण की दिशा में कोई भी कदम संबंधित समुदायों की सहमति के बिना नहीं उठाया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, आरएसएस ने स्पष्ट रूप से देश को बता दिया हैं कि वो जातिगत जनगणना के पक्ष में है। देश के संविधान और आरक्षण के पक्ष में होने वाले संघ परिवार को सामाजिक व्यवस्था में पीछे छोड़ दिये गए अपने दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग और ग़रीब-वंचित समाज की भागीदारी की चिंता है। संघ ने यह बयान वँचितों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिया है। क्योंकि सरकारी योजनाओं को ठीक से लागू करने के लिए इस तरह के आंकड़ों की जरूरत होती है। सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं के लिए विशेष रूप से जो जाति पिछड़ रही है, उन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है और इसके लिए अगर सरकार को कभी आँकड़ों की ज़रूरत है। इसलिए संघ का मानना है कि संवैधानिक आरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। संघ ने इसका हमेशा समर्थन किया है। अब चूंकि आरएसएस ने जाति आधारित जनगणना को कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में अहम बताया है तो बीजेपी को इस मामले में फ़ैसला लेने में आसानी हो सकती है।

उन्होंने आगे कहा, जातिगत जनगणना पर संघ का बयान ऐसे समय आया है, जब देश में यूपी, विहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विपक्ष इन राज्यों में भी जातिगत जनगणना को मुद्दा बना रहा है। ऐसे में संघ ने यह बयान देकर विपक्ष के इस मुद्दे की धार को खत्म कर दिया है। संघ के इस व्यान ने विपक्ष के हथियार की धार को नष्ट कर दिया हैं। क्योंकि संघ नहीं चाहता की आपसी मनमुटाव के कारण बीजेपी कमजोर हो। बीजेपी ने भी कभी जातिगत जनगणना का खुल कर विरोध नहीं किया और न खुद को इसका विरोधी बताया लेकिन अब संघ के बयान से बीजेपी के रुख में बदलाव आया है और जातिगत जनगणना पर बीजेपी का रुख बदला है। अब सरकार अगली जनगणना में इस पर बड़ा कदम उठा सकती है। यह भी संभव है कि अगली जनगणना से पहले जातिगत जनगणना पर सरकार के रुख में बदलाव आएगा। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए-2 मनमोहन सिंह की सरकार जातिगत जनगणना को लेकर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई थी। लेकिन 2011 में हुई जनगणना में जाति को नहीं जोड़ा गया। इसकी जगह पर सरकार ने सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) करायी थी लेकिन इसके आंकड़े आज तक नहीं जारी किए गए और लगातार हार से परेशान विपक्ष को अब अपनी मुक्ति का मार्ग जातिगत जनगणना, संविधान की रक्षा और आरक्षण में नजर आ रहा है। इसलिए अब विपक्षी नेता जोर-शोर से जातिगत जनगणना की वकालत कर रहे है। जबकि पिछले एक दशक से देश में जातिगत जनगणना की मांग जोर पकड़ रही है। जाति जनगणना 2021 में ही शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोरोना के चलते इसे टालना पड़ा था। अब संसद में महिलाओं को मिले 33 फीसदी आरक्षण को लागू करने के लिए भी जाति जनगणना के आंकड़े जरूरी हैं। अब खबर है कि आरएसएस की भी सहमति के बाद मोदी सरकार जाति जनगणना कराएगी। इस पर मंथन तेजी शुरू हो चुका है और जल्दी ही इसकी प्रक्रिया का आधिकारिक ऐलान होगा। यदि जरूरी होगा तो जाति का कॉलम भी जनगणना के फॉर्म में दर्ज किया जाएगा। इस संबंध में भी जल्दी ही फैसला भी हो सकता है। कहा जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व और मोदी सरकार का बदला हुआ रुख आरएसएस के स्टैंड के चलते भी है। बिहार देश का ऐसा पहला राज्य था, जहां जातिगत जनगणना कराई गई और फिर उसके आधार पर ही आरक्षण की सीमा को भी बढ़ा दिया गया। इसलिए राष्ट्रहित में हमारी सरकार से अपील हैं कि जाति जनगणना का इस्तेमाल छुआछूत के कारण पिछड़ रहे समुदाय और जातियों के कल्याण के लिए होना चाहिए।

सुभद्रा योजना, ओड़आि अस्मिता , महिला दुष्कर्म और राज्यपाल के बेटे पर हमला के मुद्दे पर कांग्रेस की प्रेस मीट

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर : कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस ओडिशा के हितों और पहचान के लिए लड़ रही है। अब 4 दिनो बाद राज्य में मोहन सरकार के 100 दिन पूरे हो जायेंगे। इस मौके पर बीजेपी सरकार की कांग्रेस ने सुभद्रा योजना, अडानी को गोपालपुर पोर्ट, एएसओ पर राज्यपाल के बेटे का हमला और उड़िया अस्मिता के मुद्दे पर प्रेजेंटेशन दिया।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सुभद्रा योजना लॉन्च की जाएगी। प्रधानमंत्री ओडिशा आएंगे। प्रधानमंत्री के दौरे पर सरकारी खजाने से हजारों करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी उनके जन्मदिन को शुभ दिन मानती है। उन्होंने कहा कि सभी महिलाओं को 50-50 हजार रुपये दिये जायेंगे। राज्य की 2 करोड़ 25 लाख महिलाओं में से 30 फीसदी महिलाओं को उम्र के आधार पर बाहर कर दिया गया। बाकी 70 फीसदी 1 करोड़ 40 लाख होगा। लेकिन यह वैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि इसमें सभी महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए, क्यों नहीं? कितनी महिलाओं को श्वेत पत्र जारी किया जाएगा? कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से पूछा है कि 833 महिलाओं में से एक महिला उद्यमी कैसे बनेगी।कांग्रेस ने फिर कहा है कि बीजेपी पूंजीपतियों की सरकार है। गोपालपुर बंदरगाह अडानी को दे दिया गया। हवाई अड्डा भी उपलब्ध कराया जाएगा। अडानी को ओडिशा की सारी संपत्ति क्यों दी जाएगी? जानकी बल्लभ पटनायक द्वारा शुरू की गई ओमफेड को भी एक निजी कंपनी को देने की योजना है। गोपालपुर और धामरा पोर्ट अडानी को देने के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन करेगी। हम अडानी के नाम पर दो एयरपोर्ट नहीं बनाएंगे। यह सरकार मोहन सरकार नहीं, बल्कि मदनी सरकार है।

इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खनिज अंतिम राज्य में मिलेगा। लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार ने इसे खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की है। इससे ओडिशा को डेढ़ लाख करोड़ का नुकसान होगा। कब आएगा ये पैसा? गवर्नर के बेटे ने अधिकारी पर बोला हमला? तब बीजेपी चुप रही। यह रूढ़िवादी अस्मिता क्या है? अजय कुमार ने कहा कि विदेशी पूंजीपति ओडिशा आकर लूटेंगे। जो सच होने जा रहा है। प्रवक्ता डॉ विश्वरंजन मोहंती ने कहा, एक पूंजीपति ओडिशा को लूटने के लिए बैठा है।

मोहन माझी सरकार में वेश्यावृत्ति अपराध नहीं है। ओडिशा उतर् प्रदेश बन गया है। राम मंदिर में काम करने वाली महिला से भी हुई बदसलूकी उन्नाव। आज भी मणिपुर जल रहा है। डबल इंजन सरकार के बाद राज्य आपदा की आग में जल रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग दम तोड़ रहा है। एनएच 55 का काम कब होगा? सस्मिता बेहेरा ने कहा, प्रधानमंत्री जवाब दीजिए।

महिलाओं को नाइट ड्यूटी से नहीं रोक सकते, उन्हें सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी; CJI ने सिब्बल को भी लिया आड़े हाथ

मंगलवार को सुनवाई के दौरान जब SC को बताया गया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने डॉक्टरों की सुरक्षा के संबंध में जो अधिसूचना जारी की है। उसमें महिला डॉक्टरों के रात्रि ड्यूटी न करने और उनकी शिफ्ट 12 घंटे से ज्यादा न होने की बात कही गई है तो कोर्ट ने आपत्ति जताते हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से कहा कि वह अधिसूचना वापस लें और उसमें सुधार करें।

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार की उस अधिसूचना पर कड़ी आपत्ति जताई जिसमें महिला डॉक्टरों की रात्रि ड्यूटी से परहेज और उनकी ड्यूटी 12 घंटे से ज्यादा न होने की बात कही गई थी। कोर्ट ने कहा महिलाओं को रात्रि ड्यूटी करने से कैसे रोका जा सकता है। किसी भी महिला से यह नहीं कहा जा सकता कि तुम रात्रि ड्यूटी नहीं कर सकतीं।

डॉक्टर, पायलेट, सशस्त्र बल सभी जगह रात्रि ड्यूटी होती है। महिला डॉक्टर हर परिस्थिति में काम करने को तैयार है और उन्हें हर परिस्थिति में काम करना चाहिए। महिलाएं रियायत नहीं बल्कि समान अवसर चाहती हैं। उन्हें रात्रि ड्यूटी से नहीं रोका जा सकता। उन्हें सुरक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है।

सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया

शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि उसे अपनी अधिसूचना ठीक करनी चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने अस्पतालों में सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ठेके पर सुरक्षा कर्मी रखने पर भी सवाल उठाए। ये टिप्पणियां और निर्देश प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कोलकाता में प्रशिक्षु डॉक्टर से दरिंदगी और हत्या के मामले में सुनवाई के दौरान मंगलवार को दिये। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है।

सिब्बल ने पीठ को भरोसा दिलाया

कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की पैरोकारी कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से कहा कि आप महिलाओं से नहीं कह सकते कि वे रात्रि ड्यूटी न करें। ये उनके कैरियर के लिए नुकसानदेह होगा। राज्य का कर्तव्य है कि वह उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए। महिलाएं कोई विशेष रियायत नहीं मांग रहीं वे बराबरी के अवसर चाहती हैं। सिब्बल ने पीठ को भरोसा दिलाया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो महिलाओं की समानता को प्रभावित करती होगी।

कोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा पर उठाए सवाल

हालांकि उन्होंने कहा कि 12 घंटे से ज्यादा ड्यूटी न होने की बात अनिवार्य न की जाए। इस पर पीठ का कहना था कि ड्यूटी के घंटे सभी डॉक्टरों के लिए तर्कसंगत होने चाहिए। अस्पताल में डॉक्टरों की

सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा ठेके पर सुरक्षा कर्मी रखे जाने के निर्णय पर पर भी कोर्ट ने सवाल उठाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि यहां पर मुद्दा डॉक्टरों की सुरक्षा का है। ठेके के सुरक्षाकर्मियों पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। डॉक्टर से दरिंदगी का आरोपी सिविल डिफेंस का ही व्यक्ति है।

डॉक्टरों से काम पर लौटने का अनुरोध

कोर्ट ने कहा कि राज्य की पुलिस को सुरक्षा में लगाया जाना चाहिए। सिब्बल ने कहा कि इनकी भी पूरी तरह जांच होती है। इसके अलावा वहां पुलिस और सीआरपीएफ तो तैनात रहेगी ही। सुरक्षा व्यवस्था ठीक करने का भरोसा दिलाते हुए सिब्बल ने जूनियर डॉक्टरों के काम पर लौटने का अनुरोध किया, साथ ही कोर्ट को भरोसा दिलाया कि अगर डॉक्टर काम पर वापस लौटते हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

बाढ़ पीड़ितों की धुकधुकी बढ़ा रहा गंगा-यमुना का विकराल रूप , बिहार में टूटा बांध; कई गांवों में घुसा पानी

बिहार में गंगा सोन पुनपुन व फल्गू समेत पहाड़ी नदियां उफनाने लगी हैं। सारण में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से दो सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। इससे दियारा क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। बक्सर में गंगा खतरे के निशान से चार सेमी नीचे है। यहां एक दर्जन से अधिक गांव पानी से घिर गए हैं।

नई दिल्ली। लगातार वर्षा से बिहार में गंगा, सोन, पुनपुन व फल्गू समेत पहाड़ी नदियां उफनाने लगी हैं। सारण में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से दो सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। इससे दियारा क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। कई सड़कों पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है।

बक्सर में गंगा खतरे के निशान से चार सेमी नीचे है। यहां एक दर्जन से अधिक गांव पानी से घिर गए हैं। चौसा के दो वार्डों के 50 से अधिक घरों में पानी प्रवेश कर गया है। वहीं चौसा-डिहरी मुख्य मार्ग पानी में डूब जाने से आवागमन ठप हो गया है। भोजपुर जिले में गंगा खतरे के निशान से 39 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। सोन नदी के जलस्तर में वृद्धि जारी है।

खालिम चक में तटबंध में दरार

रोहतास के डेहरी स्थित इंद्रपुरी बराज से मंलगवार को 3.30 लाख क्यूसेक पानी सोन नदी में छोड़ा गया। सोन में उफान के कारण औरंगाबाद जिले में टीला पर पांच भेड़ पालक करीब छह सौ भेड़ के साथ फंस गए। सूचना पर गया से एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। जहानाबाद जिले में फिर फल्गु नदी उफना गई है। हुलासगंज के वनबरिया स्थित उदेरा स्थान बराज का गेट खोल दिया गया है। उधर, नालंदा जिले में लोकाईन नदी में बाढ़ आने से मुसाढ़ी गांव के निकट का तटबंध लगभग 15 फीट टूट गया है। खालिम चक में तटबंध में दरार आ गई है। जिराईन नदी खतरे के निशान से 2.17 मीटर ऊपर बह रही है।

बाढ़ का पानी श्रीकाशी विश्वनाथ धाम परिसर तक पहुंचा

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा-यमुना और वाराणसी में गंगा का जलस्तर बीते 24 घंटे में मामूली घटा है। प्रयागराज में गंगा का जल स्तर 26 व यमुना का 30 सेमी कम हुआ है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर मंगलवार को खतरा बिंदु से 43 सेमी नीचे 70.83 मीटर पर स्थिर हो गया है। बाढ़ का पानी श्रीकाशी विश्वनाथ धाम परिसर तक पहुंच चुका है। मणिकर्णिका घाट और अस्सी की गलियों में नावें चल रही हैं।

पानी से हालात बिगड़ सकते हैं

फर्रुखाबाद में पांच सेंटीमीटर बढ़कर खतरे के निशान 137.10 मीटर पर पहुंचा गंगा का जलस्तर संकेत है कि भागीरथी का उफान अभी थमने वाला नहीं है। नरौरा बांध से गंगा में छोड़े गए 1,62,668 क्यूसेक पानी से हालात बिगड़ सकते हैं। अयोध्या, मऊ, आजमगढ़ और बलिया में लगातार खतरे के निशान के ऊपर सरयू का प्रवाह भी बाढ़ से कठिनाइयों में घिरे गांवों की परीक्षा ले रहा है।

भुबनेश्वर मे लापरवाही से गाड़ी चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कमीशनरेट पुलिस को पता चला

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेस्वर : बालको ने ट्राफिक का धज्जिआ उड़ाई । उसने यातायात नियमों का पालन नहीं किया, बल्कि यातायात पुलिस को मारने की भी कोशिश की। हैरानी की बात यह है कि कमिश्नरेट पुलिस को इसकी जानकारी तक नहीं हुई। लापरवाही से गाड़ी चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विशेष दस्ता हरकत में आया और युवक को ढूंढ निकाला। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 3 वाहनों को जब्त कर खरबनगर पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया। पुलिस ने कहा कि उन्हें मंगलवार को पेश किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 5 लोगों में से 4 नाबालिग हैं। एक लेन में और 5 लोग वापस आ गए हैं।

सोमवार का समय सुबह करीब 9:30 बजे का होगा. झारपाड़ा मस्जिद बस्ती से 4 लेन निकलीं। वाहन टाटा सफारी (OR14X4728), क्रेटा (OD02 CR092), I-20 और महेंद्र XUV (OD02CM4616) थे जिनमें 12 से 14 लोग सवार थे। उन्होंने अपना सिर सनरूफ और दरवाजों से बाहर निकाला, विशिष्ट झंडा लहराया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और सड़कों पर आतंक मचाया। झारपाड़ा से ये 4 लेन सत्यनगर बिग बाजार होते हुए सार्वजनिक सड़क पर पहुंचीं और बानिबिहार की ओर जा रही थीं।उनके आतंक से सड़क पर चल रहे लोग भयभीत हो गए। यदि उनके सामने कोई वाहन आ रहा होता तो वे अभद्र भाषा में गाली-गलौज करते। आश्चर्य की बात यह है कि नाबालिगों का यह अल्पसंख्यक वर्ग सबसे अधिक विपुल था। अगर कहीं ट्रैफिक जाम हो तो वे फुटपाथ पर गाड़ी चलाते थे। किसी की गति 60 किमी/घंटा थी तो किसी की गति 80 किमी/घंटा थी। ये सब देखकर सड़क से गुजर रहे लोगों के पास वीडियो बनाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा।

वे सत्यनगर बिग बाजार के पास एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को मारने की कोशिश कर रहे थे। ट्रैफिक अधिकारी वीएचएफ में किसी को सूचित किए बिना इस बारे में चुप रहे। उन्होंने शहीदनगर आईडीबीआई स्ट्रीट और रूपाली स्ट्रीट के बीच तांडव चलाया। वह बहुत खतरनाक ढंग से गाड़ी चला रहा था। फिर वे वानिबिहार और रसूलगढ़ होते हुए झारपाड़ा गए।

बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 तारीख की सुबह भुवनेश्वर आ रहे हैं। जनपथ स्थित होटल में तमाम नेता और मंत्री ठहरे हुए हैं। पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। 81 प्लाटून पुलिस बल शहर की सुरक्षा कर रहा है। पुलिस तीन दिन से सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रख रही है। सोमवार को कारकेड रिहर्सल भी हुई। इसी बीच सोमवार की सुबह 9 से 9:30 बजे तक उन्होंने पुलिस को खुली चुनौती दी और सड़क पर आतंक मचाया। या खरबेह नगर थाना पुलिस कुछ भी पता नहीं लगा सकी। प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले राजधानी की सड़कों पर इस तरह की आतंकी वारदातें पुलिस की कार्यप्रणाली पर उंगली उठाती हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023